RNI No. : TNHIN/2013/5252 ■ वर्ष - 13 ■ अंक - 146 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- चेन्नई » शनिवार » 20-12-2025 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 जीतन राम मांझी के वीडियो से बिहार में फिर भड़का 'वोट चोरी' विवाद

6 ओमान के साथ व्यापार समझौता, कितना फायदेमंद?

7 अभिनेत्री श्रीलीला ने एआई के दुरुपयोग पर जताई नाराजगी

फर्स्ट टेक

नामक्कल किडनी गिरोह मामले में एक और बिचौलिया गिरफ्तार

नामक्कल (तमिलनाडु)/भाषा। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने किडनी बेचने वाले गिरोह में शामिल होने के संदेह में शुक्रवार को पल्लीपलायम में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। कार्तिकेयन नाम के इस व्यक्ति पर बिचौलिया होने का संदेह है। वह इरोड जिले का निवासी है। एसआईटी पहले ही चार अन्य बिचौलियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तमिलनाडु के नामक्कल जिले में पिछले दिनों किडनी बेचने में संलिप्त एक गिरोह का पता लगा था जहां दलालों ने कथित तौर पर गरीब हथकरघा और कपड़ा श्रमिकों (जिनमें से कई महिलाएं थीं) को निशाना बनाया।

बांग्लादेश में ईशनिंदा के आरोप में हिंदू व्यक्ति की पीटकर हत्या

ढाका/नई दिल्ली/भाषा। बांग्लादेश में ईशनिंदा के आरोप में हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति की पीटकर हत्या कर दी गई और उसके शव को आग लगा दी गई। यह देश में धार्मिक अल्पसंख्यक के खिलाफ हिंसा की नवीनतम घटना है। 'बांग्ला ट्रिब्यून' समाचार पोर्टल के अनुसार मृत व्यक्ति की पहचान दीपू चंद्र दास (25) के रूप में हुई, जो मैमनसिंह शहर में एक कारखाने में काम करते थे। अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को एक बयान में मैमनसिंह शहर में हिंदू समुदाय के व्यक्ति की पीटकर हत्या किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार ने कहा, इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

निफ्ट ने 2026-27 बैच के लिए प्रवेश परीक्षा आवेदन शुल्क घटाया

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) ने 2026-27 सत्र के लिए फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क कम कर दिया है। वस्त्र मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सत्र 2026-27 के लिए ओपन, ओबीसी (एनसीएल) और ओपन-ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 3,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए कर दिया गया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी (पीडब्ल्यूडी) में आने वाले उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1,500 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दिया गया। प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 6 जनवरी, 2026 है, (7 से 10 जनवरी तक विलंब शुल्क के साथ) और परीक्षा की तिथि 8 फरवरी, 2026 है।

20-12-2025 सूर्यास्त 5:58 बजे | 21-12-2025 सूर्योदय 6:36 बजे

BSE	NSE
84,929.36	25,966.40
(+447.55)	(+150.85)

सोना	चांदी
13,850 रु.	207,343 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

चतुर्युग देश दशा

था एक समय जब कहलाता,
यह देश कभी योद्धाओं का।
सोने की चिड़िया लुटी तभी,
यह हो गया सिर्फ अभावों का।
मुगलों अंग्रेजों के युग में,
यह था मेहनतकश गाँवों का।
आजादी बाद दलों में बँट,
यह हो गया सिर्फ चुनावों का।।

पारंपरिक चिकित्सा को जनता का विश्वास जीतना होगा : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पारंपरिक चिकित्सा को वह मान्यता नहीं मिलती जिसकी वह हकदार है और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए उसे विज्ञान के माध्यम से जनता का विश्वास जीतना होगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि अनुसंधान को मजबूत करने, डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने और एक विश्वसनीय नियामक ढांचा विकसित करने से पारंपरिक चिकित्सा को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा की बात आती है तो सुरक्षा और प्रमाण से संबंधित प्रश्न हमेशा उठते हैं।

मोदी ने कहा, ''भारत इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन में आप सभी ने अश्वगंधा का उदाहरण देखा है। सदियों से इसका उपयोग हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में होता रहा है। कोविड-19 के दौरान इसकी वैश्विक मांग तेजी से बढ़ी और कई देशों में इसका उपयोग शुरू हुआ।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने शोध और साक्ष्य-आधारित सत्यापन के माध्यम से अश्वगंधा को बढ़ावा दे रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐतिहासिक आयुष पहल की भी शुरुआत की, जिनमें 'माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल' (एमएआईएसपी) भी शामिल है। उन्होंने 'आयुष मार्क' का भी अनावरण किया, जिसे आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए एक वैश्विक मानक के रूप में देखा जा रहा है। मोदी ने योग प्रशिक्षण पर डब्ल्यूएचओ की तकनीकी रिपोर्ट और 'फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच: 11 इयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष' नामक पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।

प्रौद्योगिकी में उभरती चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि लोक सेवा आयोगों को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने के साथ-साथ पारदर्शिता को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर दक्ष सिविल सेवकों की टीम विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यहां लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि लोक सेवा आयोगों को भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के पहलू को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा, ''लोक सेवा आयोगों को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर दक्ष सेवकों की टीम विकसित करने की आवश्यकता है।''

मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जनहितैषी नीतियों को लागू करने के लिए स्थायी कार्यपालिका में शामिल सिविल सेवकों की सत्यनिष्ठा, संवेदनशीलता और योग्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सर्वोपरि हैं तथा इनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुर्मू ने कहा कि कौशल और योग्यता की कमी को प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य रणनीतियों के माध्यम से दूर किया जा सकता है लेकिन सत्यनिष्ठा की कमी गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकती है, जिन पर नियंत्रण पाना असंभव हो सकता है।

राष्ट्रपति ने लोक सेवा आयोगों से उम्मीदवारों के नैतिक दृष्टिकोण को समझने में सहायक साधनों और तकनीकों की तलाश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोगों को लैंगिक संवेदनशीलता को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। मुर्मू ने कहा, ''मुझे बताया गया है कि सम्मेलन में प्रौद्योगिकी, कानूनी पहलुओं और भर्ती की पूरी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्श से आयोगों के समक्ष मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए भविष्योन्मुखी और उपयोगी समाधान निकलेंगे।''

राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत के विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था और अपार विविधता से संपन्न राष्ट्र होने के नाते सभी स्तरों पर सबसे प्रभावी शासन प्रणालियों की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोक सेवा आयोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे और उनके द्वारा चयनित तथा निर्देशित सिविल सेवकों के भविष्य के लिए तैयार टीम के निर्माण में योगदान देंगे।

कर्नाटक के मंत्री ने भूमि हड़पने के आरोपों को खारिज किया

बेलगावी (कर्नाटक)/भाषा। कर्नाटक के मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने शुक्रवार को उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उन्होंने एक गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, और जोर देकर कहा कि जमीन पर उनके परिवार का स्वामित्व दशकों पहले कानूनी रूप से साबित हो चुका है। कोलार तालुक के गरुड़नपाल्या गांव में कथित तौर पर भूमि कब्जाने को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच, मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस विवाद से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौड़ा ने कर्नाटक विधानसभा में एक स्वैच्छिक बयान में कहा, ''पिछले दो-तीन दिनों से कोलार तालुक के गरुड़नपाल्या गांव में सरकारी जमीन पर कथित कब्जे को लेकर चर्चा चल रही है। इस मामले में मेरा नाम भी घसीटा गया है।'' भाजपा ने बुधवार को गौड़ा पर कोलार जिले में 21 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि अभिलेखों में इसे मूल रूप से एक झील और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज किया गया था।

अपनी परियोजनाओं में हरित क्षेत्रों को भी शामिल करें रियल एस्टेट डेवलपर : अमित शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रियल एस्टेट कंपनियों से अपनी परियोजनाओं की योजना बनाते समय हरित क्षेत्रों को भी जगह देने का आग्रह किया और निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण देने की जरूरत पर बल दिया। शाह ने यहां रियल एस्टेट निकाय क्रेडाई के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम (रेरा) ने डेवलपरों के कामकाज को सुगम बनाने के साथ घर खरीदारों के हितों की भी रक्षा की है। उन्होंने कहा कि विभिन्न निर्माण सामग्रियों पर जीएसटी दरें घटाए जाने से परियोजनाओं की लागत घटाने में मदद मिलेगी।

शाह ने कहा, लागत में कमी आने से बिल्डर ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे। गृह मंत्री ने रेरा कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि जब यह कानून लाया गया था, तब उद्योग में कई आशंकाएं थीं। लेकिन आज कोई इनकार नहीं कर सकता कि रेरा ने डेवलपरों के सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

शाह ने कहा, जब हम नियमन को प्रतिबंध के रूप में देखते हैं, तभी समस्या पैदा होती है। नियमन हमेशा व्यापार के अवसर बढ़ाने, विश्वसनीयता मजबूत करने और ग्राहकों को बेहतर सुविधाओं की गारंटी देने में मदद करता है।

गश्ती पोत 'अमूल्य' को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के तेज गति वाले गश्ती पोत 'अमूल्य' को भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) में शामिल कर लिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के मुताबिक 'अमूल्य' निगरानी, खोज एवं बचाव, तस्करी विरोधी अभियान और प्रदूषण निवारण सहित कई प्रकार के मिशनों को अंजाम देगा, जिससे देश के पूर्वी तट की सुरक्षा में भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) की भूमिका को मजबूती मिलेगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 'अमूल्य' सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने तथा राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने की आईसीजी की इच्छा और प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

अधिकारी ने कहा, '' गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित यह 51 मीटर लंबा एफपीवी (त्वरित गश्ती पोत) स्वदेशी जहाज निर्माण में एक नया मानदंड स्थापित करता है। ''

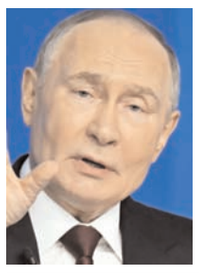

यूक्रेन में क्रेमलिन के सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए जाएंगे : पुतिन

मॉस्को/एपी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि मॉस्को की सेना यूक्रेन के युद्धक्षेत्र में आगे बढ़ रही है और क्रेमलिन के सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए जाएंगे। पुतिन ने अपने वर्षांत संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि रूसी सेनाओं ने ''रणनीतिक पहल को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है'' तथा वर्ष के अंत तक और अधिक लाभ प्राप्त होंगे।

क्रेमलिन का आशय रूस की सरकार या सत्ता प्रतिष्ठान से होता है। वर्ष 2022 में संघर्ष के शुरुआती दिनों में, यूक्रेन की सेना ने रूस की विशाल और बेहतर अस्त्रों से लैस सेना के राजधानी कीव पर कब्जा करने के प्रयास को विफल कर दिया था। हालांकि, लड़ाई जल्द ही भीषण संघर्ष में बदल गई।

, और मॉस्को की सेना ने वर्षों से

'वीबी- जी राम जी' विधेयक :

'मनरेगा में घपले करने वाले लोगों का पेट दर्द हो रहा है'

इंदौर (मध्यप्रदेश)/भाषा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद से पारित 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक 2025' को शुक्रवार को देश के हित में बताया और कांग्रेस की अगुवाई वाली पिछली सरकार पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि 'जी राम जी' विधेयक से केवल उन लोगों का पेट दर्द हो रहा है जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) योजना में भ्रष्टाचार करके ग्रामीणों की मजदूरी ''चुरा'' लिया करते थे। सिंधिया ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा कि 'जी राम जी' विधेयक को लेकर कोई विवाद नहीं है और संसद में इसे पूर्ण बहुमत के साथ परित किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का पेश यह विधेयक देश हित में है तथा इसके कारण रोजगार बढ़ने से किसानों और युवाओं का भला होगा। उन्होंने कहा,कांग्रेस ने जब मनरेगा योजना पेश की थी, तब इसके तहत 10,000 करोड़ रुपये की राशि भी नहीं दी जाती थी, जबकि 'जी राम जी' विधेयक में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

सिंधिया ने कांग्रेस की अगुवाई वाली पिछली सरकार पर परोक्ष प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि पहले कुछ लोग मनरेगा योजना के लिए आवंटित सरकारी राशि में घपले करते थे और जाली बिलों के जरिये इस योजना के हितग्राहियों की मजदूरी चुरा लिया करते थे। उन्होंने कहा कि 'जी राम जी' विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के बाद केवल इन लोगों का पेट दर्द कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा,देश लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये लोग देश को जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। इनकी नकारात्मक सोच को देश की जनता ने बार-बार जवाब दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 'जी राम जी' विधेयक को लेकर नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं।

पंड्या के रिकॉर्ड प्रदर्शन से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर श्रृंखला जीती

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अहमदाबाद/भाषा। हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा के अर्धशतकों के बाद वरुण चक्रवर्ती के चार विकेट की मदद से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पांचवें और आखिरी टी20 मैच में शुक्रवार को 30 रन से हराकर वर्ष 2025 का अंत श्रृंखला 3-1 से जीतकर किया ।

पंड्या ने अपना अर्धशतक सिर्फ 16 गेंदों में बनाया जो भारत के लिये दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है । वहीं तिलक वर्मा ने 73 रन जोड़े जिसकी मदद से भारत ने पांच विकेट पर 231 रन बनाये । जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत अच्छी की और क्विंटोन डिकॉक (65) के क्रीज पर रहते टीम जीत की ओर बढत रही थी लेकिन आखिरी सात विकेट 81 रन के भीतर गंवाकर आठ विकेट पर 201 रन ही बना सकी । भारत के लिये जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में 17 रन देकर दो विकेट लिये ।

डिकॉक ने अर्शदीप सिंह को दो ओवर में छह चौके और एक छक्का लगाकर पावरप्ले में जबर्दस्त शुरूआत की । उन्हें हालांकि दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिल सका और रीजा हेंडरिक्स 13 रन बनाकर आउट हो गए । वरुण की गेंद पर मिडविकेट में शिवम दुबे ने एक हाथ से उनका शानदार कैच लपका ।

डेवाल्ड ब्रेविस (31) के साथ डिकॉक ने दूसरे विकेट के लिये 23 गेंद में 51 रन जोड़े । बुमराह ने ऐसे में डिकॉक का एक हाथ से रिटर्न कैच लेकर भारत को मैच में लौटाया । इसके बाद उन्होंने ब्रेविस को भी आउट किया ।

कॉन्क्लेव

19 दिसंबर 2025 को जारी इस तस्वीर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में आयोजित क्रेडाई नेशनल कॉन्क्लेव 'विकसित भारत 2047' के दौरान।

भारत-ओमान व्यापार समझौता तीन महीने के भीतर लागू होने की संभावना है : गोयल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत और ओमान मुक्त व्यापार समझौते को अगले तीन महीनों के भीतर लागू करने की कोशिश करेंगे।

दोनों देशों के बीच 18 दिसंबर को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत, ओमान ने अपनी 98 से अधिक शुल्क श्रेणियों या उत्पाद श्रेणियों पर शून्य शुल्क की पेशकश की है। इससे भारत के 99.38 प्रतिशत निर्यात को ओमान में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की जाएगी।

रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, चमड़ा, जूते, खेल के सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, औषधि, चिकित्सकीय उपकरण और मोटर वाहन सहित सभी प्रमुख श्रम-प्रधान क्षेत्रों को पूर्ण रूप से शुल्क मुक्त कर दिया गया है। वर्तमान में ओमान में इन वस्तुओं पर पांच से 100 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगता है।

दूसरी ओर, भारत अपनी कुल शुल्क श्रेणियों (12,556) में से 77.79 प्रतिशत पर शुल्क उदारीकरण की पेशकश कर रहा है। यह मूल्य के हिसाब से ओमान से भारत के आयात का 94.81 प्रतिशत हिस्सा है।

ओमान ने आखिरी बार कोई व्यापार समझौता अमेरिका के साथ किया था। ओमान-अमेरिका व्यापार समझौते को 2006 में अंतिम रूप दिया गया था, हालांकि इसे लागू जनवरी 2009 में किया गया। गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा, '' ओमान के मंत्री और मैंने इस बात पर चर्चा की है कि हम इस समझौते को तीन महीने के भीतर लागू करने की कोशिश करेंगे।''

भारतीय व्यवसायों के लिए ओमान में निवेश के संभावित क्षेत्रों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस्पात, ऊर्जा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं।

मैं विकास के लिए भाजपा में शामिल हुई : प्रज्ञा सातव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

छत्रपति संभाजीनगर/भाषा। विधान परिषद सदस्य पद और कांग्रेस से इस्तीफा देकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के एक दिन बाद प्रज्ञा सातव ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने विकास के हित में ही पाला बदला है। उन्होंने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि 'सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमेशा उनके आदर्श रहेंगे'।

दिवंगत राजीव सातव की पत्नी प्रज्ञा सातव बृहस्पतिवार को भाजपा में शामिल हुई थीं। इस दौरान भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद थे।

राजीव सातव को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के बीच प्रज्ञा का पाला बदलना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने मुंबई से लौटने के बाद हिंगोली में मराठी समाचार चैनल एबीजे माझा से कहा, मैं राजीव सातव के विकास के सपने को साकार करने के लिए भाजपा में शामिल हुई हूं। मैं भाजपा में केवल विकास के एजेंडे के लिए ही शामिल हुई हूं। कलमनुरी में सिंचाई और किसानों से संबंधित मुद्दों में काफी काम रुका हुआ है।

राजीव सातव 2009 में हिंगोली जिले के कलमनुरी से विधायक थे। वे 2014 में हिंगोली से लोकसभा सदस्य भी रहे। उनका निधन मई 2021 में हुआ।

प्रज्ञा ने कहा कि समृद्धि एक्सप्रेसवे की वजह से उन्हें मुंबई से हिंगोली जल्दी वापस आने में मदद मिली।

समृद्धि एक्सप्रेसवे, मुंबई और विदर्भ के नागपुर के बीच एक नियंत्रित पहुंच वाला कॉरिडोर है, जिसे अक्सर देवेंद्र फडणवीस सरकार की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में से एक बताया जाता है।

विधान परिषद की पूर्व सदस्य ने कहा कि उन्होंने इस तरह के विकास में योगदान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। उन्होंने कांग्रेस से सब कुछ मिलने के बावजूद सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने को लेकर पार्टी नेताओं द्वारा की जा रही आलोचना पर कहा, मैं मानती हूं कि कांग्रेस ने ही मुझे विधान परिषद का सदस्य बनाया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमेशा मेरे आदर्श रहेंगे।

प्रज्ञा ने दावा किया कि वह बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं।

मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति बेनकाब : सुरजेवाला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी नेताओं- सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र को अदालत द्वारा खारिज किए जाने से नरेन्द्र मोदी सरकार की ''प्रतिशोध की राजनीति'' बेनकाब हो गई है। सुरजेवाला ने इसे ''राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई'' करार देते हुए कहा कि अदालत ने 16 दिसंबर को ईडी के मामले को खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने के लिए एक हथियार के रूप में किया गया।

कांग्रेस नेता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला ''कानूनी रूप से निराधार और राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है।''

सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पिछले 11 वर्षों में विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने अदालत की उन टिप्पणियों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपना पहले का रुख बदलते हुए 2021 में धनशोधन की जांच शुरू की थी।

सुरजेवाला ने कहा कि अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि 2014 से 2021 के बीच न तो सीबीआई और न ही ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया था, क्योंकि कोई अपराध नहीं पाया गया था।

फरवरी में रविवार के दिन बजट पेश कर सकती हैं सीतारमण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अगर संसदीय परंपरा का पालन किया गया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट रविवार के दिन पेश कर सकती हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

साल 2017 से बजट एक फरवरी को पेश किया जाता रहा है और अगले साल इस दिन रविवार है। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''ये फैसले संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति उचित समय पर लेती है।'' नरेन्द्र मोदी नीत राजग सरकार में बजट पेश करने के लिए एक फरवरी की तारीख तय की गई, ताकि एक अप्रैल को नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ बजट को लागू किया जा सके। एक अधिकारी के अनुसार, ''आम बजट प्रस्तुत करने के लिए हमने तारीख तय कर रखी है। रविवार की अवधारणा तो अंग्रेजों द्वारा लाई गई है।''

साल 2017 से पहले, आम बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था, और संसद नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की समेकित निधि से पैसे निकालने के लिए लेखानुदान पारित करती थी।

बाकी वित्तीय वर्ष के लिए बजट को बाद में संसद द्वारा मंजूरी दी जाती थी, जब अलग-अलग विभागों की अनुदान मांगों की संबंधित संसदीय स्थायी समितियों द्वारा जांच कर ली जाती थी।

वर्ष 2017 में, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को आम बजट पेश करने और नए वित्तीय वर्ष शुरू होने से काफी पहले, मार्च के अंत तक इसे संसद से मंजूर करवाने की प्रथा शुरू की।

संसद की बैठकें खास परिस्थितियों में रविवार को भी होने के उदाहरण हैं। साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान और 13 मई, 2012 को संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए रविवार के दिन बैठकें आयोजित की गई थीं।

आईबीएम 50 लाख भारतीय युवाओं को एआई, साइबर सुरक्षा तकनीक में प्रशिक्षित करेगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 2030 तक भारत में 50 लाख लोगों को कृत्रिम मेधा (एआई), साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण देगी।

कंपनी ने बताया कि यह योजना 'आईबीएम कौशल निर्माण' कार्यक्रम के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना और लोगों के लिए उन्नत डिजिटल कौशल और रोजगार योग्यता के अवसर बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के तहत आईबीएम विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में अपने शैक्षिक प्रयासों का विस्तार करेगी कंपनी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के सहयोग से व्यावहारिक एआई प्रशिक्षण, संकाय सशक्तिकरण कार्यक्रम, हैकाथॉन और इंटर्नशिप आयोजित करेगी। आईबीएम के चेयरमैन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अरविंद कृष्णा ने कहा, भारत में एआई और क्वांटम क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने की प्रतिभा व महत्वाकांक्षा है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में दक्षता आर्थिक प्रतिस्पर्धा, वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करेगी। उन्नत कौशल तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाकर, हम युवाओं और छात्रों को भारत के विकास को आगे बढ़ाने, नवाचार करने और गति प्रदान करने में सक्षम बना रहे हैं।

ईडी ने बैंक 'धोखाधड़ी' मामले में अनिल अंबानी के बेटे से पूछताछ की

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार को यहां पूछताछ की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 34-वर्षीय व्यक्ति का बयान धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया और शनिवार को भी यह सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है।

ईडी की जांच यस बैंक से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार, 31 मार्च, 2017 तक बैंक का रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का ऋण था और यह आंकड़ा एक वर्ष के भीतर (31 मार्च, 2018 तक) दोगुना होकर 13,000 करोड़ रुपए हो गया।

इन कंपनियों में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) शामिल थीं।

गुजरात रियल एस्टेट के विकास के लिए बेहतर जगह : मुख्यमंत्री पटेल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को रियल एस्टेट कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि राज्य में व्यापार के बड़े अवसर हैं और यहां परियोजनाओं के लिए समय पर अनुमति दी जाती है। पटेल ने कहा कि गुजरात रियल एस्टेट गतिविधियों के लिए सबसे अच्छा गंतव्य बन गया है और साथ ही सुनियोजित शहरी विकास के लिए आदर्श भी है।

रियल एस्टेट कंपनियों के शीर्ष निकाय क्रेडाई के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने डेवलपर्स से गुजरात में गिफ्ट सिटी और आगामी धोलेरा औद्योगिक शहर में व्यावसायिक अवसर तलाशने का आग्रह किया। उन्होंने रियल एस्टेट कंपनियों से पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को साकार करने में रियल एस्टेट क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पटेल ने सरकार और रियल एस्टेट उद्योग को मिलकर 'सभी के लिए आवास' का लक्ष्य पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने डेवलपर्स से अपनी परियोजनाओं को डिजाइन और निर्माण करते समय भारत की विरासत को ध्यान में रखने का भी आग्रह किया, भले ही वे विदेशों की निर्माण प्रौद्योगिकी से प्रेरणा लें।

पटेल ने कहा, रियल एस्टेट क्षेत्र के कारोबारियों को सतत और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान देना चाहिए। घरों, कार्यालयों और मॉल का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल होना आवश्यक है।

गोवा मुक्ति दिवस

मुख्यमंत्री सावंत ने लोगों से राज्य को स्वच्छ और शांत बनाए रखने का आग्रह किया

पणजी/भाषा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को उद्योगों और नागरिकों से तटीय राज्य को साफ रखने तथा इसकी सुंदरता एवं शांति को बरकरार रखने की अपील की। पणजी के पास राज्यस्तरीय 'गोवा मुक्ति दिवस' परेड को संबोधित करते हुए सावंत ने कहा कि राज्य में स्वच्छता बनाए रखना पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों और अन्य अतिथियों की उपस्थिति में तिरंगा फहराने के बाद परेड का निरीक्षण किया और 'गार्ड ऑफ ऑनर' लिया। सावंत ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया।

गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1961 में पुर्तगालियों से राज्य को मुक्त कराने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन विजय' की सफलता का प्रतीक है। वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर इस राज्य के लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर गोवा के मेरे सभी भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं।'' उन्होंने कहा, आज हम उन वीर योद्धाओं के साहस और बलिदान को नमन करते हैं जिन्होंने भारत में गोवा को उसका उचित स्थान दिलाया। शर्मा ने आशा व्यक्त की कि राज्य प्रगति और विकास की राह पर आगे बढ़ता रहेगा।

बिना तलाक लिए विवाहित व्यक्ति 'लिव-इन' संबंध में नहीं रह सकता

प्रयागराज/भाषा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक विवाहित व्यक्ति अपनी पत्नी/पति से तलाक लिए बगैर कानूनी रूप से 'लिव-इन' संबंध में नहीं रह सकता। अदालत ने इस टिप्पणी के साथ ही एक जोड़े की सुरक्षा के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और यह मौजूदा जीवन साथी के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती।

याचिकाकर्ताओं ने इस अनुरोध के साथ अदालत का रुख किया था कि दोनों बालिग हैं और पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं और उनके जीवन को प्रतिवादी से खतरा है।

वहीं दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील ने याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि इन याचिकाकर्ताओं का कृत्य अवैध है क्योंकि प्रथम याचिकाकर्ता पहले से ही दिनेश नाम के व्यक्ति की पत्नी है और उसने तलाक नहीं लिया है।

प्रारंभिक आकलन के बाद इंडिगो मामले की जांच का निर्णयः सीसीआई चेयरपर्सन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रतिस्पर्धा आयोग की चेयरपर्सन स्वनीत कौर ने शुक्रवार को कहा कि प्रारंभिक आकलन के आधार पर सीसीआई ने हाल ही में हुई उड़ान संबंधी व्यवधानों के बाद इंडिगो के संचालन की जांच करने का निर्णय लिया है। कौर ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि विशिष्ट जानकारी के आधार पर आयोग ने अपने प्रारंभिक आकलन में मामले की आगे जांच करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, हमारे पास कुछ जानकारी है, जिसके आधार पर मामला आयोग के समक्ष रखा गया था। आयोग का मानना है कि प्रारंभिक आकलन के आधार पर हम मामले की और अधिक विस्तार से जांच कर सकते हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या आयोग पूरे विमानन क्षेत्र की जांच करेगा, तो उन्होंने कहा, नहीं। हमने केवल प्राप्त जानकारी की जांच शुरू की है और यह जानकारी केवल इंडिगो से संबंधित है। यह पूछे जाने पर कि क्या प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा चार के तहत इंडिगो मामले की भी जांच करेगा तो कौर ने कहा, इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह अधिनियम बाजार में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है क्योंकि एयरलाइन की बाजार हिस्सेदारी लगभग 65 प्रतिशत है।

ओमान ने पहली बार किसी देश को संगमरमर ब्लॉक के निर्यात की अनुमति दी : गोयल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत भारत को संगमरमर के ब्लॉक आयात करने की अनुमति दे दी है। इससे भारत को संगमरमर ब्लॉक के आयात के लिए तुर्किये पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत और ओमान के बीच सीईपीए पर 18 दिसंबर को मस्कट में हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अगले तीन महीनों में लागू होने की संभावना है।

गोयल ने कहा कि ओमान आमतौर पर संगमरमर के ब्लॉक के निर्यात की अनुमति नहीं देता है और भारत इस तरह की सुविधा पाने वाला पहला देश है। उन्होंने कहा, इससे भारत में संगमरमर की घरेलू प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अब हम तैयार मार्बल आयात करने की बजाय भारत में रोजगार सृजन करेंगे और भारत निर्मित मार्बल टाइल्स एवं फ्लोरिंग उपलब्ध होगी। इससे तुर्किये से होने वाले आयात में भी कमी आएगी।

वर्तमान में भारत का कच्चा संगमरमर ब्लॉक आयात लगभग 13 लाख टन है, जो मुख्यतः तुर्किये, इटली और वियतनाम से आता है। देश में संगमरमर उद्योग प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में केंद्रित है। गोयल ने यह भी बताया कि ओमान के साथ हुए समझौते से मांस के निर्यात के लिए हलाल प्रमाणन की पारस्परिक मान्यता की व्यवस्था भी सुगम होगी। खाड़ी देश एवं अन्य इस्लामी देश हलाल उत्पादों के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि ओमान ने इस समझौते के तहत भरोसा दिलाया है कि वहां निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों को केवल निर्धारित संख्या में ही ओमानी नागरिकों को नियुक्त करना होगा, जबकि बाकी कर्मचारी भारत से हो सकते हैं। गोयल ने बताया, इस तरह ये निवेश हमारे लोगों के लिए रोजगार पैदा करेंगे। यह पहली बार है कि ओमान ने ऐसा किया है, और यह सुविधा स्थायी होगी। ओमान में कानून बदलने पर भी यह प्रावधान सीईपीए में बना रहेगा। उन्होंने समझौते को 'बाध्यकारी' बताते हुए कहा कि इसमें लेखा, कराधान, वास्तुकला, चिकित्सा एवं नर्सिंग जैसे कुशल पेशेवरों के लिए आसान प्रवेश एवं ठहराव की शर्तें भी शामिल हैं।

गिरिराज सिंह जैसे नेता भारत को 'कौरव राज्य' बनाना चाहते हैं : महबूबा मुफ्ती

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्रीनगर/भाषा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जैसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता भारत को 'कौरव राज्य'बनाना चाहते हैं, जहां महिलाओं का अनादर किया जाता है। मुफ्ती ने यहां पत्रकारों से कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह महात्मा गांधी की भूमि है, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन गिरिराज सिंह जैसे नेता इसे 'कौरव राज्य' में बदलना चाहते हैं, जिसमें कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया था।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सोमवार को पटना में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला के चेहरे से नकाब हटाने की घटना के बाद विवाद खड़ा हो गया। गिरिराज सिंह ने बृहस्पतिवार को कुमार का बचाव करते हुए कहा कि यह महिला पर निर्भर है कि वह सरकारी नौकरी को ठुकरा दे या 'जहन्नुम में जाए'।

मुफ्ती ने सिंह की मानसिकता की तुलना कौरवों की मानसिकता से करते हुए कहा, महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। द्रौपदी मुस्लिम नहीं थीं और न ही घूंघट ओढ़ती थीं, फिर भी उनका चीर हरण किया गया और गिरिराज जैसे कौरव तालियां बजाते व हंसते रहे। वे आज भी ऐसा ही करते हैं, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे भाजपा नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है।

आवासीय परिसर में घुसे तेंदुआ ने चार लोगों पर हमला किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

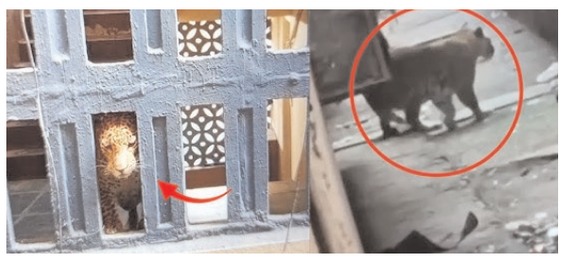

ठाणे (महाराष्ट्र)/भाषा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भायंदर इलाके में शुक्रवार सुबह आवासीय सोसायटी में भटककर आए तेंदुआ के हमले में चार लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घायलों में इमारत के निवासी और राहगीर शामिल हैं। आवासीय इलाके में तेंदुआ की मौजूदगी से वहां अफरा-तफरी मच गई।

एक अधिकारी ने बताया, ''भायंदर पूर्व के तलाव मार्ग स्थित घनी आबादी वाले आवासीय इलाके में तड़के एक तेंदुआ भटककर आ गया और उसने कुछ राहगीरों पर हमला कर दिया। इसके बाद वह 'पारिजात' नामक इमारत में घुस गया जहां उसने कुछ निवासियों पर भी हमला किया। उन्होंने बताया कि तेंदुआ कुछ समय के लिए सोसायटी के एक कमरे में छिपा रहा। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में तेंदुआ को संकरे रास्ते और सीढ़ीनुमा स्थान से गुजरते हुए देखा गया। अधिकारी ने बताया, तेंदुआ के अचानक दिखाई देने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग डरकर अपने घरों में चले गए। उन्होंने बताया कि घायलों को बाद में नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है।

अधिकारी के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही नवघर थाना और भायंदर अग्निशमन दल के कर्मी मौके पर पहुंचे और इलाके को सुरक्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में ठाणे के वन विभाग और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) की टीम भी शामिल हुई।

एक अधिकारी ने बताया, ''तेंदुआ को घेरकर इमारत के एक फ्लैट में सुरक्षित रूप से बंद कर दिया गया है ताकि आगे किसी को नुकसान न हो। एहतियात के तौर पर पूरी इमारत और आसपास के इलाके को घेर लिया गया है और निवासियों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है।''

मानद वन्यजीव संरक्षक एवं गैर सरकारी संगठन 'रेस्किंक एसोसिएशन फॉर वाइल्डलाइफ वेलफेयर' (आरएडब्ल्यूडब्ल्यू) के संस्थापक पवन शर्मा ने कहा, हमारी टीम इलाके में स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर बचाव सहायता तैयार रखी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोगों से घरों में रहने और भीड़ न लगाने की अपील की गई है। तेंदुआ को सुरक्षित रूप से पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

महिलाएं स्वाभाविक रूप से नेता बनने के लिए प्रेरित होती हैं : किरण बेदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अहमदाबाद/भाषा। देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने शुक्रवार को कहा कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से नेता बनने के लिए प्रेरित होती हैं क्योंकि उनमें ईमानदारी, सहानुभूति, निष्ठा और करुणा जैसे गुण होते हैं। बेदी ने 'शी लीड्स 2.0 : कार्यबल में महिलाओं को सशक्त बनाना - समावेशिता और आर्थिक परिवर्तन का नेतृत्व करना' नामक एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।

इस कार्यक्रम का आयोजन महिलाओं के नेतृत्व, समावेशिता और आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में आयोजित किया गया।

पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल बेदी ने कहा, ''अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें और सीखते रहें। महिलाओं में ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें नेतृत्व के लिए उपयुक्त बनाते हैं। वास्तव में, उनमें अक्सर ऐसे गुण होते हैं जो पुरुषों में नहीं होते। महिलाओं में सहानुभूति, करुणा और संवेदनशीलता होती है। एक नेता, चाहे वह पुरुष हो या महिला, उसमें टीम निर्माण, सहयोगात्मकता, प्रतिस्पर्धा न करने, दूसरों का ख्याल रखने और अपने काम को भली-भांति जानने जैसे गुण होने चाहिए।'' उन्होंने कहा कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से नेता बनने के लिए प्रेरित होती हैं क्योंकि वे स्वभाव से अधिक ईमानदार, मानवीय और निष्ठावान होती हैं।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की पहली महिला अधिकारी बेदी ने कहा, ''माता-पिता को शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करके लड़कियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। महिलाएं केवल शादी करने और मां बनने के लिए ही बड़ी नहीं होतीं। उन्हें पहले आत्मनिर्भर बनना होगा और फिर यह तय करना होगा कि वे अपना जीवन कैसे जीना चाहती हैं।'' उन्होंने बताया कि महिलाओं के नेतृत्व का विकास काफी हद तक माता-पिता के पालन-पोषण, शिक्षा और व्यक्तिगत आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। बेदी ने इस बात पर बल दिया, ''एक महिला की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से उसके सपनों और स्वयं के प्रति उसकी दृष्टि की ओर केंद्रित होती है। महिलाओं में नेतृत्व इसी दृष्टि पर निर्भर करता है।''

श्रीराम फाइनेंस अपनी 20% हिस्सेदारी जापानी कंपनी एमयूएफजी बैंक को 39,618 करोड़ रुपये में बेचेगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/चेन्नई। वित्तीय सेवा कंपनी श्रीराम फाइनेंस के निदेशक मंडल ने शेयर के तरजीही निर्गम के माध्यम से जापान स्थित एमयूएफजी बैंक को 39,618 करोड़ रुपये (करीब 4.4 अरब अमेरिकी डॉलर) के निवेश पर 20 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के परिणामस्वरूप वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह होगा।

कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि इस निवेश के परिणामस्वरूप एमयूएफजी बैंक को पूर्णतः चुकता आधार पर 20 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त होगी। इसमें कहा गया कि एमयूएफजी बैंक के साथ निश्चित समझौतों पर हस्ताक्षर करने से भारत के ऋण एवं वित्तीय सेवा क्षेत्र के मूलभूत सिद्धांतों और भविष्य की वृद्धि क्षमता में विश्वास मजबूत होता है। साथ ही यह एसएफएल के पूंजी आधार को भी मजबूत करेगा और इसकी वृद्धि की गति को तेज करेगा। कंपनी सूचना के अनुसार एमयूएफजी बैंक द्वारा प्रस्तावित निवेश शेयरधारकों की मंजूरी, नियामक स्वीकृतियों और प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है।

चेन्नई में भूख हड़ताल पर बैठीं 500 से अधिक परिचारिकाएं हिरासत में ली गईं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। स्थायी रोजगार और अन्य लाभों की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठीं 550 से अधिक परिचारिकाओं को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, परिचारिकाओं को बृहस्पतिवार रात उस समय हिरासत में लिया गया जब उन्होंने धरना स्थल से हटने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुक्रवार तड़के उन्हें केलमबक्कम बस टर्मिनस पर छोड़ दिया गया, लेकिन परिचारिकाओं ने बस टर्मिनस पर ही अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

सूत्रों के अनुसार, इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन 'तमिलनाडु नर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन' द्वारा किया गया था, जिसमें मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (एमआरबी) की लगभग 600 परिचारिकाओं ने हिस्सा लिया। एसोसिएशन के निर्वाचित सदस्यों ने 'पीटीआई वीडियो' को बताया कि इन परिचारिकाओं की नियुक्ति 2015 में एक 'समेकित वेतन प्रणाली' के तहत इस वादे के साथ की गई थी कि दो साल बाद उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया जाएगा। उन्होंने द्रमुक सरकार पर चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। परिचारिकाओं की मुख्य मांगों में सभी एमआरबी नर्सों के लिए स्थायी रोजगार का दर्जा, 'समान काम के लिए समान वेतन' लागू करना आदि शामिल हैं।

शबरीमला सोना मामला :

टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष वासु और अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज

कोच्चि/भाषा। केरल उच्च न्यायालय ने शबरीमला में भगवान अयप्पा मंदिर से सोना गायब होने से संबंधित मामले में आरोपी टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष एन. वासु और बोर्ड के दो पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिकाएं बुधवार को खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने वासु, तिरुवनंतपुरम के पूर्व आयुक्त के. एस. बायजू और त्रावणकोर देस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मुरारी बाबू को राहत देने से इनकार कर दिया।

उच्च न्यायालय ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसाईटी) शबरिमला से सोना गायब होने के मामले की जांच कर रहा है। एसआईटी ने श्रीकोविल (गर्भगृह) और द्वारपालकों के स्वर्ण-जड़ित हिस्सों से सोना गायब होने के संबंध में दो मामले दर्ज किए हैं।

आरोप है कि मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी ने 2019 में इलेक्ट्रोप्लेटिंग' के दौरान सोने की प्लेटें हटा दी थीं। इस मामले में अब तक टीडीबी के दो पूर्व अध्यक्षों और चार पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

वर्षों से कमल हासन की कला और विविध प्रकार के किरदारों का प्रशंसक रहा हूं : अनुपम खेर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/चेन्नई। अभिनेता अनुपम खेर ने दक्षिण भारतीय फिल्मों के कलाकार कमल हासन से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा और उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से 'एक' करार दिया। खेर ने शुक्रवार को 'फेसबुक' पर हासन के साथ एक तस्वीर साझा की और कहा कि वह वर्षों से अभिनेता के काम के प्रशंसक रहे हैं। दोनों अभिनेताओं की मुलाकात दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई थी।

खेर ने पोस्ट में लिखा, दिल्ली हवाई अड्डे पर भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक कमल हासन जी से मिलकर बहुत खुशी हुई! मैं वर्षों से उनकी कला और विविध अभिनय का प्रशंसक रहा हूं। मैंने उनसे एक अभिनेता के रूप में बहुत कुछ सीखा है। शानदार अभिनय की सूची में उनका काम अनगिनत है। खेर ने बताया कि हासन के साथ उनकी बहुत ही 'सार्थक बातचीत' हुई।

उन्होंने लिखा, हम हवाई अड्डे के लाउंज में करीब एक घंटे तक बैठे रहे। उस एक घंटे में ऐसा लगा जैसे हमने पूरी जिंदगी की बातें कर ली हों। इतने सारे विषय, विश्व सिनेमा, के. बालाचंद्र सर, जीवन के सबक, पसंदीदा किताबें और बेशक महान रजनीकांत सर। यह एक बहुत ही सार्थक बातचीत थी। सर, आपके ज्ञान, स्नेह और सराहना के लिए धन्यवाद! प्यार, सम्मान और दुआएं हमेशा आपके साथ!

मनरेगा को बदले जाने के विरोध में द्रमुक गठबंधन ने 24 को प्रदर्शन का आह्वान किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाए गए केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में 24 दिसंबर को राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है।

गठबंधन दल के जिला सचिवों, विधायकों, स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के साथ-साथ एक सौ दिन के रोजगार सुनिश्चित करने वाली मौजूदा योजना के लाभार्थियों को भी आंदोलन में शामिल किया जाएगा। गठबंधन ने वर्ष 2025 के विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक'' (वीबी- जी राम जी विधेयक) को वापस लेने की मांग की है। नये विधेयक के तहत मनरेगा को समाप्त कर नयी ग्रामीण रोजगार व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया है।

गठबंधन ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा, चौबीस दिसंबर को सुबह 10 बजे राज्य की राजधानी में तथा पार्टी के सभी स्थानीय स्तरों पर 100-दिवसीय रोजगार योजना के लाभार्थियों को जुटाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।''

विज्ञप्ति में कहा गया, ''आइए, तमिलनाडु के लोगों को धोखा दे रही भारतीय जनता पार्टी-नीत केंद्र सरकार और उसे समर्थन देने वाली अन्नाद्रमुक के खिलाफ आवाज उठाएं।''

इससे पहले, 18 दिसंबर को तमिलनाडु सरकार ने केंद्र की नयी ग्रामीण रोजगार योजना पर कड़ा ऐतराज जताया था।

मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि प्रस्तावित कानून करोड़ों ग्रामीण गरीबों की आजीविका को खतरे में डाल देगा, खासकर तमिलनाडु जैसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में, और इससे केंद्र तथा राज्यों के बीच के संबंधों पर भी दबाव पड़ेगा।

केनरा बैंक ने आंध्र प्रदेश के तिरुचानूर स्थित एक मंदिर को नकदी गिनने की मशीन दान की

चेन्नई/तिरुपति। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने तिरुचानूर स्थित श्री पद्मावती अम्मावरु मंदिर को नकदी गिनने की एक मशीन (कैश काउंटिंग मशीन) दान की है। श्री पद्मावती अम्मावरु मंदिर की ओर से बृहस्पतिवार देर रात जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा यह मशीन मंदिर के उप कार्यकारी अधिकारी हरिंद्रनाथ को सौंपी गयी।

तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) श्री वेंकटेश्वर मंदिर और उससे जुड़े अन्य तीर्थस्थलों का आधिकारिक संरक्षक है।

दरे ने ट्रेनों पर पत्थरबाजी के खिलाफ कार्रवाई तेज की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। दक्षिणी रेलवे (दरे) के चेन्नई डिवीजन ने चलती ट्रेनों पर पथराव के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति को दोहराया है। यह अपराध रेल अधिनियम, 1989 के तहत दंडनीय है और यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे संपत्ति के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के समन्वय से, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने निगरानी बढ़ा दी है, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 153 और 154 के तहत 37 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

अधिकारियों ने गौर किया है कि कई घटनाएं नाबालिगों द्वारा रेलवे ट्रैक के पास खेलने से जुड़ी होती हैं, अक्सर वे इसे शरारत समझते हैं। ऐसे कृत्यों से यात्रियों को गंभीर चोटें आ सकती हैं और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, चेन्नई डिवीजन ने चिन्हित जोखिम वाले क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है। स्कूलों, पर्चों और सामुदायिक वार्ताओं के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना।

दरे ने पटरियों के संवेदनशील स्थानों के पास चेतावनी बोर्ड लगाना शुरू कर दिए है। यात्रियों और स्थानीय लोगों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए सभी को प्रोत्साहित कर रही है। बच्चों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए माता-पिता और अभिभावकों को शिक्षित कर रही है। संवेदनशील क्षेत्रों का सीसीटीवी की मदद से निगरानी की जा रही है।

दरे के चेन्नई मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी ए. एलुमलाई ने विज्ञप्ति में बताया कि पत्थर फेंकना दंडनीय अपराध है और बिना किसी अपवाद के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माता-पिता और अभिभावकों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि बच्चे रेलवे ट्रैक के पास न खेलें। यात्रियों और आम जनता से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें और पत्थर फेंकने की किसी भी घटना या संदिग्ध गतिविधि की सूचना रेलवे हेल्पलाइन 139 पर दें। चेन्नई डिवीजन इस बात पर जोर देता है कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है , और सुरक्षित और निर्बाध ट्रेन संचालन के लिए जनता के सहयोग के साथ-साथ निरंतर प्रवर्तन आवश्यक है।

अभिनेत्री हमला प्रकरण : दो दोषियों ने अधीनस्थ अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने 2017 के अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए गए छह लोगों में से दो की अपीलों पर शुक्रवार को सरकार से उसका रुख पूछा। इस मामले में अभिनेता दिलीप समेत चार आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया था। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने प्रदीप और सलीम एच की अपीलें स्वीकार कर लीं, जिन्होंने अपनी दोषसिद्धि और 20 साल के कारावास की सजा को चुनौती दी है। सलीम एच को वदिवल सलीम के नाम से भी जाना जाता है।

दोनों अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से अपीलें लंबित रहने के दौरान उनकी सजा निलंबित रखने का भी अनुरोध किया है। उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को इन अपीलों पर अपनी आपत्तियां दाखिल करने के लिए समय दिया और उनपर अगली सुनवाई की तारीख चार फरवरी, 2026 तय की।

एर्नाकुलम जिला एवं प्रधान सत्र न्यायालय की न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने 12 दिसंबर को प्रदीप और सलीम के अलावा, सुनील एनएस उर्फ पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी और विजयेश वीपी को भी सामूहिक बलात्कार के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। जिला एवं प्रधान सत्र न्यायालय ने आठ दिसंबर को अभिनेता दिलीप समेत चार आरोपियों को बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों ने 17 फरवरी, 2017 को कथित तौर पर जबरन अभिनेत्री की कार में घुसकर दो घंटे तक उसे अपने कब्जे में रखा। इस घटना ने केरल को झकझोर दिया था। मुख्य आरोपी पल्सर सुनी ने अभिनेत्री का यौन उत्पीड़न किया और चलती कार में अन्य दोषियों की मदद से इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया।

कर्नाटक निजी चिकित्सा संस्थान (संशोधन) विधेयक पारित हुआ

बेलगावी। विधानसभा द्वारा अनुमोदित कर्नाटक निजी चिकित्सा संस्थान (संशोधन) विधेयक-2025, विधान परिषद में पारित हो गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कर्नाटक निजी चिकित्सा संस्थान अधिनियम, 2007 (कर्नाटक अधिनियम 21 ऑफ 2007) में संशोधन करना आवश्यक समझा है। इसके अंतर्गत 'निजी चिकित्सा संस्थान' की परिभाषा में 'मानसिक स्वास्थ्य संस्थान' को शामिल किया गया है, पंजीकरण एवं शिकायत निवारण प्राधिकरण में भारतीय चिकित्सा संघ से एक सदस्य और किसी पंजीकृत चिकित्सा संस्थान या चिकित्सा चिकित्सकों के संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को मनोनीत किया गया है, पंजीकरण एवं शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकृत करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, अस्थायी रूप से पंजीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों की एक सूची प्रकाशित की गई है जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है, निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा स्थायी पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए आवेदन हेतु पूर्व-आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है और आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

मैं पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा करूंगा : सिद्दरामय्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेलगावी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने शुक्रवार को दोहराया कि वह पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा करते हुए पद पर बने रहेंगे और इसके साथ ही कांग्रेस आला कमान के समर्थन पर विश्वास जताया। उत्तर कर्नाटक के विकास से जुड़े मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा के दौरान सिद्दरामय्या ने कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वह केवल ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री के पद पर हैं।

विपक्षी भाजपा विधायकों के इस सवाल के जवाब में कि क्या उनके कार्यकाल के दौरान उत्तरी कर्नाटक के लिए सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे होंगे, उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि (कांग्रेस) आला कमान मुझे पांच साल का कार्यकाल पूरा करने देगी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आला कमान मेरे साथ है, मैं आला कमान के फैसले का पालन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के वी सुनील कुमार ने उनके भविष्य पर सवाल उठाया, तो मुख्यमंत्री ने कहा, मैं मुख्यमंत्री हूं। अगर आला कमान फैसला करता है, तो मैं भविष्य में भी मुख्यमंत्री रहूंगा। जब विपक्षी सदस्यों ने सिद्दरामय्या और उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के बीच बारी-बारी से मुख्यमंत्री पद संभालने के ''सत्ता-साझेदारी'' पर सवाल उठाया, तो उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ढाई साल तक के लिये मुख्यमंत्री रहूंगा। सुनील कुमार ने कहा, हम चाहते हैं कि आप उत्तर कर्नाटक क्षेत्र के लिए किए गए सभी वादे पूरे करें। आपको यह स्पष्ट करना होगा कि क्या आप भविष्य में भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। इस पर सिद्दरामय्या ने जवाब दिया, मैं भविष्य में भी मुख्यमंत्री बना रहूंगा।

उन्होंने भाजपा के नेताओं को यह भी याद दिलाया कि उनके दिग्गज नेता बी एस येदियुरप्पा ने पूरे कार्यकाल का वादा किया था, लेकिन उन्हें पद छोड़ना पड़ा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, हमारे पास कोई निर्देशक नहीं है। हम निर्माता, निर्देशक और अभिनेता हैं, जबकि आपके पास एक निर्देशक है। सिद्दरामय्या के ये बयान राज्य में मुख्यमंत्री परिवर्तन की अटकलों के बीच आए हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने पांच वर्षीय कार्यकाल का आधा समय पूरा कर लिया है। यह बातचीत पार्टी के भीतर स्थिरता का माहौल बनाने और अपनी स्थिति मजबूत करने के सिद्दरामय्या के प्रयासों को उजागर करती है।

विपक्ष के विरोध के बीच विधान परिषद में भड़काऊ भाषण विधेयक पारित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक विधान परिषद में शुक्रवार को विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (एस) के कड़े विरोध के बीच भड़काऊ भाषण पर अंकुश लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया।

भाजपा और जद(एस) ने इस विधेयक को 'अत्याचारी', 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला' और राजनीतिक प्रतिशोध का 'खतरनाक हथियार' करार दिया। गृह मंत्री जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक भड़काऊ भाषण एवं घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक पर सदन के भीतर विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच मतदान हुआ। भाजपा और जद(एस) सदस्यों के विरोध के बावजूद यह विधेयक बृहस्पतिवार को विधानसभा में पारित हो गया था। विपक्ष ने विधेयक को वापस लेने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून 'पुलिस राज' और 'अघोषित आपातकाल' की स्थिति पैदा करेगा, जहां आलोचना को भी भड़काऊ भाषण माना जा सकता है। मंत्री ने कहा कि विधेयक में घृणा अपराध के लिए एक वर्ष की कैद और अधिकतम सात वर्ष की कैद के साथ 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है। बार-बार अपराध करने पर अधिकतम सात वर्ष की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना होगा।

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस)
(जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान), भारत सरकार
गेट नं. 5, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्टाफ चयन परीक्षा (ईएसएसई) – 2025

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRSs) में **शिक्षकीय** एवं **गैर-शिक्षकीय** पदों पर भर्ती हेतु ESSE-2025 की घोषणा की गई है।

प्रथम चरण (Tier-I) परीक्षा में छात्रावास अधीक्षक, स्टाफ नर्स (महिला), **कनिष्ठ सचिवालय सहायक** एवं **प्रयोगशाला परिचारक** पदों की परीक्षा **21 दिसंबर 2025** को आयोजित की जाएगी।

उम्मीदवार अपने प्रवेश-पत्र निम्न लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं:

https://examinationservices.nic.in/AdmitCardService/Admitcard/Login?appref no=102992511

भविष्य की अद्यतनों हेतु उम्मीदवारों को वेबसाइट **www.nests.tribal.gov.in** पर नियमित रूप से विज़िट करने की सलाह दी जाती है।

जारीकर्ता: **NESTS**

महिला सशक्तीकरण से ही समग्र विकास का सपना होगा पूरा : भजनलाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधी आबादी के सशक्तीकरण से ही समग्र विकास का सपना पूरा किया जा सकता है। हमारी सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार अपनी नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से महिला उत्थान के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में हमारी आधी आबादी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

शर्मा ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत शुक्रवार को धौलपुर के पचगांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी शक्ति का सदैव सम्मान रहा है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की नारी शक्ति को सम्मान और गरिमा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने नारी शक्ति को राष्ट्रीय प्रगति का आधार बनाया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने वाली नीतियां लागू की हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिछले 11 वर्षों में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। साथ ही, जल जीवन मिशन के तहत 13 लाख 59 हजार ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज में बालिकाओं के प्रति भेदभाव की मानसिकता को समाप्त करने का काम किया है। इसी तरह उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि, लखपति दीदी तथा महिलाओं के जन धन खाते खोलने जैसी योजनाओं से महिलाओं का आर्थिक भविष्य सुरक्षित हुआ है।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भी हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और उनके सशक्तीकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 19 लाख 45 हजार महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गईं। साथ ही, लाडो प्रोत्साहन योजना से अब तक 4 लाख 60 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इसी तरह 10 लाख 51 हजार साइकिलें और 39 हजार 586 स्कूटियां देकर बालिका शिक्षा को गति दी गई है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली 5 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किया है। मा वाउचर योजना से अब तक 2 लाख 26 हजार महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट तथा 65 एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया है। हमारी सरकार के कार्यकाल में महिला अत्याचार के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने धौलपुर जिले के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। धौलपुर में 1 लाख 62 हजार महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही, जिले की 30 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी योजना से लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने कहा कि जिले में राजकीय महाविद्यालय सैंपउ, सरमथुरा और राजकीय कन्या महाविद्यालय मरैना के भवनों का निर्माण, डेढ़ लाख विद्यार्थियों को निशुल्क यूनिफॉर्म तथा जल जीवन मिशन के तहत लगभग 58 हजार नल कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में 717 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 5 हजार 663 आवासों का निर्माण प्रगतिरत है। इसी तरह पार्वती नदी पर संजापुरी आश्रम के पास एनीकट का निर्माण, पार्वती मुख्य नहर एवं माकरा ब्रांच का जीर्णोद्धार, मचकुंड धाम में सौंदर्यीकरण एवं विकास से संबंधित अनेक कार्य करवाए गए हैं। जिले में बुनियादी ढांचा, पेयजल, चिकित्सा, वन, ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।

शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में गत सरकार के 5 वर्षों से ज्यादा काम किए हैं। गत सरकार के पांच साल के समय केवल 1 हजार 478 गांव खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ प्लस) हो पाए, जबकि हमने केवल दो साल में 41 हजार गांवों को ओडीएफ प्लस बना दिया है। इसी तरह पूर्ववर्ती सरकार ने पांच साल में 21 हजार छात्राओं को स्कूटी वितरित की, जबकि हम लगभग 40 हजार छात्राओं को स्कूटियां दे चुके हैं। हमने इन दो साल में 3 लाख 37 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया, जबकि गत सरकार ने पूरे पांच साल में 2 लाख 35 हजार युवाओं को ही कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पांच साल में सिर्फ 986 स्कूली विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप वितरित किए, जबकि हम 89 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप वितरित कर चुके हैं। इसी तरह हमारी सरकार ने पिछले दो साल में प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता में 6 हजार 363 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की है, जबकि गत सरकार ने 5 साल में केवल 3 हजार 952 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आज महिला घर की चौखट से निकलकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी कर रही है। अब महिला लाभार्थी ही नहीं, बल्कि नीति निर्माता भी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नारी सशक्तीकरण को सिर्फ एक नीति ही नहीं बल्कि एक मिशन बनाया है। उन्होंने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बालिका को सम्मान, पोषण और सुरक्षा मिल रही है तथा समाज में बेटी के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ रही है।

'विधायक निधि' में भ्रष्टाचार के आरोप; सदाचार समिति के सामने पेश हुए तीनों विधायक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। 'विधायक निधि' जारी करने के बदले कमीशन लेने के आरोप के मामले में तीन विधेयक शुक्रवार को यहां राजस्थान विधानसभा की सदाचार समिति के सामने पेश हुए।

समिति के अध्यक्ष कैलाश वर्मा ने बताया कि विधायकों ने अपनी बात रखी, कुछ दस्तावेज पेश किए तथा और समय मांगा। उन्होंने बताया कि समिति ने इन विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए और समय दिया है। उल्लेखनीय है कि समिति ने इस मामले में राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रेवंतराम डांगा, कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और निर्दलीय विधायक रितु बनावत को बुधवार को नोटिस जारी करके शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा था।

वर्मा ने बताया कि तीनों विधायक आज विधानसभा में समिति के सामने अलग अलग पेश हुए और तीनों ने अपना पक्ष रखा एवं कुछ दस्तावेज पेश किए। उन्होंने बताया कि साथ ही समिति के सदस्यों द्वारा मांगी गई जानकारी व अपनी ओर से और साक्ष्य पेश करने के लिए और समय मांगा। उन्होंने बताया कि विधायक डांगा ने 15 दिन, बनावत ने 10 दिन व विधायक जाटव ने सात दिन का और समय मांगा है। उन्होंने बताया कि समिति ने उन्हें इसकी अनुमति दी है। वर्मा ने कहा, ''स्टिंग आपरेशन करने वाले पत्रकार को भी समिति ने नोटिस देकर बुलाया है। एक बार वह भी आज आएंगे तो उनका पक्ष भी समिति जानेगी।''

एक अखबार ने अपने 'स्टिंग ऑपरेशन' में इन तीनों विधायकों पर 'विधायक निधि' जारी करने के बदले कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। उल्लेखनीय है कि सरकार ने विधायकों द्वारा 'विधायक निधि' जारी करने के बदले कमीशन लेने के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की है। वहीं, इस जांच का नतीजा आने तक तीन विधायकों के विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमएलए एलएडी) खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के बाद की गई जिसमें खींवसर से भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत पर विधायक निधि से रकम मंजूर करने के बदले 'कमीशन' लेने का आरोप लगाया गया था। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा व मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने-अपने विधायकों को नोटिस जारी किए हैं।

राजस्थान सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया

स्थानीय निकाय चुनाव अगले साल अप्रैल तक कराए जाएंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नयी दिल्ली/जयपुर। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि राज्य में पंचायत और नगर निगम चुनाव अगले साल अप्रैल तक करा लिए जाएंगे। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक संयम लोढा की याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें उन्होंने नगर निकाय चुनाव तत्काल कराए जाने का आग्रह किया था और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने में अनुचित देरी का आरोप लगाया था।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि जारी परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने वाली है और स्थानीय निकायों के चुनाव उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर कराए जाएंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि इस स्तर पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, और यदि किसी भी कारण से चुनाव में देरी होती है, तो संबंधित पक्ष उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 14 नवंबर के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, हमें लगता है कि परिसीमन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल, 2026 तक इसे पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। हमें इस विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता।

उच्च न्यायालय ने 14 नवंबर को राज्य सरकार को लंबित पंचायत और नगर निकाय चुनाव एक साथ कराने तथा अगले वर्ष 15 अप्रैल तक पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया था। इसने अधिकारियों को दोनों निकायों के लिए परिसीमन प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूरा करने के लिए कहा था। राज्य में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव होगा।

मूल्य आधारित हो विकास और नवाचार : देवनानी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षा, विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार मूल्य आधारित, समयानुकूल व युगानुकूल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि शोध और अनुसंधान समाज और मानव जीवन को लाभ देने वाले हों। देवनानी ने कहा कि मानव जीवन में चारित्रिक दृढता, नेतृत्व कौशल और सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ लक्ष्य तय करके काम करने चाहिए, इसी से समाज निर्माण की दिशा तय हो सकेगी। वे यहां एक महिला महाविद्यालय में दो दिवसीय बहुविषयक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। देवनानी ने कहा कि नये परिप्रेक्ष्य में आज का विद्यार्थी आज का ही नागरिक है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को विश्लेषण के लिए सोच बढानी होगी। उन्होंने कहा कि भारत और भारत के नागरिक होने पर गर्व की अनुभूति का एहसास नई पीढ़ी को भी कराना होगा।

उन्होंने नैतिक मूल्यों के साथ ही नवाचार करने पर जोर देते हुए कहा कि सांस्कृतिक सनातन संस्कृति के मूल्यों से नई पीढ़ी को भी परिचित कराएं ताकि युवाओं में संवेदनशीलता, आदर, सहृदयता, ईमानदारी, विश्वास, करूणा और सहयोग की भावना का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को जीवन का अंग बनाएं और उसे व्यवहार में लाएं। देवनानी ने कहा कि आज का बदलता परिवेश कृत्रिम मेधा (एआई) का है। उन्होंने कहा, एआई से जब हम किसी संदर्भ में जानकारी लेते हैं तो वहां से गैर भावनात्मक जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर अधिक से अधिक भारतीय परिवेश वाला 'कंटेंट' प्रसारित करें ताकि जब कोई एआई से जानकारी ले तो उसमें भारतीय परिवेश के संबंध में सही जानकारी प्राप्त हो सके।

उन्होंने कहा कि नाम से ही भाव आए यह नवाचार में आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, विकास, तकनीकी में किये जाने वाले नवाचार मूल्य आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक परिवर्तन का युग है, भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता और नैतिकता का होना जरूरी है। देवनानी ने कहा कि जर्मनी और जापान में वैज्ञानिक अथर्ववेद की सूक्तियों पर अनुसंधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि, चिकित्सा, शिक्षा में आधुनिक तकनीक अपनाएं और नैतिक मूल्यों के साथ विकास और नवाचार करें। एक आधिकारिक बयान के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नारी शक्ति को विश्व में भारतीय संस्कृति के प्रसार का वाहक बनना होगा। देवनानी ने सम्मेलन में नवाचार, प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण और मानव मूल्यों के सतत भविष्य पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया।

उद्घाटन समारोह में राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. अल्पना कटेजा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलगुरु प्रो0 अनिल कुमार राय विशिष्ट अतिथि थे। मुख्य वक्ता मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के पूर्व महानिदेशक डॉ. लक्ष्मण सिंह राठौड़ थे।

मुख्य सचिव ने की 4 से 6 जनवरी तक होने वाले 'राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026' की तैयारियों की समीक्षा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में 'राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026' की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जयपुर के जेईसीसी, सीतापुरा में 4 से 6 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले 'राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट' में 10 हजार से अधिक प्रतिभागियों का शामिल होना प्रस्तावित है, जिनमें देश-विदेश के वक्ता एवं निवेशक, केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि, स्टार्टअप संस्थापक, उद्यमी, छात्र, शैक्षणिक संस्थान, कॉर्पोरेट प्रतिनिधि तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओड़िशा एवं गुजरात सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जो स्टार्टअप, निवेश, नवाचार एवं उद्यमिता से जुड़े सत्रों में सहभागिता करने के साथ ही तकनीकी नवाचारों के साक्षी बनेंगे।

मुख्य सचिव ने कहा कि यह आयोजन राजस्थान को डिजिटल नवाचार, स्टार्टअप इकोसिस्टम एवं तकनीकी निवेश के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सशक्त पहचान दिलाने का अवसर प्रदान करेगा।

उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को निर्देश दिए कि आयोजन से जुड़ी सभी तैयारियां निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाए और आयोजन को भव्य स्वरूप दिया जाए। साथ ही उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पर्यटन एवं कला-संस्कृति विभाग द्वारा राजस्थान पवेलियन, एयरपोर्ट हेल्पडेस्क एवं अतिथि स्वागत की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। नगरीय विकास विभाग द्वारा शहर की सड़कों की साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण एवं आवश्यक नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। गृह विभाग को सुरक्षा, ट्रैफिक एवं पार्किंग प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। सामान्य प्रशासन विभाग को प्रोटोकॉल व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा अतिथियों हेतु आवास एवं वाहन प्रबंधन के निर्देश दिए गए।

महिला ने कुल्हाड़ी से पति की हत्या की

जयपुर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में शुक्रवार को एक महिला ने अपने पति की कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस ने बताया इसके बाद महिला ने कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि ग्रामीणों ने उसे बचा लिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना आज रावतभाटा पुलिस थाने के तमलाव गांव में हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला को गांव वालों ने कुएं से निकाला और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस उपाधीक्षक शंकर लाल मीणा ने बताया कि आरोपी लाड बाई ने अपने पति मोहन गुर्जर (45) पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद लाड बाई बंजारा बस्ती के पास एक कुएं में कूद गई। उन्होंने बताया कि ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रस्सी की मदद से उसे बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जानकारी से पता चला है कि महिला पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी। पुलिस ने बताया कि मौके पर मोबाइल फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मीणा ने बताया कि पुलिस हर कोण से मामले की जांच कर रही है।

मौत के 36 दिन बाद, राजस्थान के युवक का पार्थिव शरीर सऊदी अरब से लाया गया

जोधपुर। सऊदी अरब में मृत्यु हो जाने के 36 दिन बाद बृहस्पतिवार को 19 वर्षीय रमेश कुमार मेघवाल के शव को राजस्थान के बालोतरा जिला स्थित उनके पैतृक गांव मेघवालों की धाणी लाया गया। प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के फेर में फंसे रहने के बाद, रमेश का शव बृहस्पतिवार दोपहर जयपुर हवाई अड्डे पर लाया गया, जहां परिजनों को शव सौंप दिया गया। इस मामले में बृहस्पतिवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को रमेश के शव को उसके पैतृक गांव ले जाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। परिजन ने रमेश की मृत्यु की संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और पोस्टमार्टम की मांग की।

मनरेगा' का नाम ही नहीं बदला, पूरी मूल संरचना ही बदल गई : टीकाराम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर । राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 'मनरेगा' को लेकर दावा किया कि सरकार ने इस योजना का सिर्फ नाम ही नहीं बदला है, बल्कि इसकी पूरी मूल संरचना को ही बदलकर रख दिया है। पहले इस योजना के तहत काम के आधार पर श्रमिकों को रोजगार दिया जाता था। लेकिन, अब इसमें बजट के आधार पर श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। इससे इसका पूरा मूल ढांचा ही बदल गया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि मनरेगा के तहत 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता था। अब सरकार ने इस योजना पर बड़ा प्रहार किया है। इस योजना ने कोरोना काल में श्रमिकों की काफी मदद की थी। पहले इस योजना का पूरा बजट केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता था। अब नए बिल के बाद राज्य सरकार को भी अपने बजट का कुछ हिस्सा इस योजना को संचालित करने में लगाना होगा। मनरेगा की योजना श्रमिक केंद्रित थी। इस योजना में दो महीने की भी पाबंदी लगा दी गई है। अब इस योजना के नए प्रावधान में कहा गया है कि फसल के समय में श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश की मौजूदा सरकार हर चीज का वाणिज्यीकरण कर रही है। अगर हर चीज का इसी तरह से वाणिज्यीकरण होता रहेगा, तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे? जवाब स्पष्ट है कि कुछ भी देकर नहीं जाएंगे। अगर हमारे पूर्वजों ने इसी तरह का कृत्य किया होता, तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं होता। हम अब इस तरह की स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने वाले नहीं हैं। केंद्र सरकार को आम जनता से कोई लेना-देना नहीं है। यह सरकार सिर्फ अपने लोगों को ही फायदा पहुंचाने में जुटी रहती है।

मौलिक कर्तव्यों का पालन कर बनें आदर्श नागरिक : गुप्ता

जयपुर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में 1 दिसंबर से संचालित शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुक्रवार को सफलतापूर्वक समापन किया गया। समापन समारोह में आयोग के सदस्य अशोक कुमार गुप्ता ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आयोग राज्य में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निगरानी संस्था के रूप में कार्य करता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में प्रयासरत रहता है। उन्होंने कहा कि जहां हम अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, वहीं आदर्श नागरिक बनने के लिए संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों का पालन करना भी समान रूप से आवश्यक है। गुप्ता ने विद्यार्थियों के अनुशासन, सहभागिता और सीखने की इच्छा की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। महानिरीक्षक पुलिस हिंगलाजदान ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी पेशे में सफल होने के लिए व्यक्ति का भावनात्मक रूप से सुदृढ़ होना और सही सोच व संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने जीवन और कार्यक्षेत्र में कानून का पालन करते हुए आदर्श आचरण अपनाएँ और सदाचार के मार्ग पर चलते हुए देश के उत्तम नागरिक बनें। समापन कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने न्याय व्यवस्था और मानवाधिकारों से संबंधित समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने 'मृत्युदंड मानव अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं', 'समकालीन समय में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता' तथा 'मानव अधिकार अधिनियम 1993 को 2019 में किए गए संशोधनों से किस हद तक अधिक प्रभावी बनाया गया है'इन महत्वपूर्ण विषयों पर पक्ष और विपक्ष में तर्कपूर्ण प्रस्तुतियाँ दीं।

लोकसभा में विपक्ष के बर्ताव के कारण नहीं हो सकी वायु प्रदूषण पर चर्चा : रीजीजू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने शुक्रवार को विपक्ष पर वायु प्रदूषण के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं होने देने का आरोप लगाया और कहा कि 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक' पर चर्चा के दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने 'अस्वीकार्य व्यवहार' किया। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने यह दिखाया कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी खतरे के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं चाहते थे।

संसद के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद पारंपरिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सत्र को 'बहुत उत्पादक' बताया। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में चर्चा के बाद आठ विधेयक पारित किए गए और ये कानून आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' की गति

तेज करेंगे। उन्होंने कहा, ''लेकिन लोकसभा में विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन -ग्रामीण (वीबी- जी राम जी) विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष का व्यवहार अस्वीकार्य था। कुछ विपक्षी सदस्य तो टेबल ऑफिस और (लोकसभा) महासचिव की मेजों के ऊपर खड़े हो गए। कुछ कांग्रेस सदस्यों ने यह भी कहा कि प्रदूषण पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई।''

वायु प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो पाने पर खेद व्यक्त करते हुए रीजीजू ने कहा कि सरकार प्रदूषण पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार थी। इस विषय पर वक्ता के तौर पर प्रियंका गांधी वाद्रा (कांग्रेस), कनिमोझी (द्रमुक) और बांसुरी स्वराज (भाजपा) के नाम सूचीबद्ध थे।

रीजीजू ने कहा, ''हम प्रदूषण पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन कांग्रेस ने अन्य सदस्यों को आसन के समीप (वीबी-जी राम जी विधेयक को लेकर) प्रदर्शन करने के लिए उकसाया। उन्होंने कागज उछाले, कागज के हवाई जहाज बनाकर फेंके और मेजों के ऊपर खड़े होकर कार्यवाही बाधित की। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि ऐसी चालों से उन्हें वोट नहीं मिलेंगे। केवल अच्छे कामों से ही उन्हें वोट मिलेंगे।''

बिहार में सभी पुलिस लाइन में खुलेंगे आवासीय विद्यालय: सम्राट चौधरी

पटना/भाषा। बिहार में सभी 40 पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। यह घोषणा राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को की। चौधरी पुलिस मुख्यालय स्थित सरदार पटेल भवन के सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान बिहार पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत सेवा के दौरान विभिन्न कारणों से मृत 36 पुलिसकर्मियों के परिजनों के बीच बीमा राशि से संबंधित चेक का वितरण किया गया। उपमुख्यमंत्री, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने संयुक्त रूप से चेक वितरित किए। इस अवसर पर कुल 25 करोड़ रुपए की राशि पीड़ित परिजनों के बीच वितरित की गई।

बिहार के गृहमंत्री चौधरी ने कहा कि पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण के दौरान उनके बच्चों की पढ़ाई सबसे बड़ी चिंता होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन में आवासीय विद्यालय खुलने से इस समस्या का समाधान होगा और बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी आठ घंटे से अधिक की होती है और प्रदेश की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए सरकार आवासन, भोजन व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रही है। 30 जनवरी से पहले पटना पुलिस लाइन की तर्ज पर राज्य की शेष 39 पुलिस लाइन में 'जीविका दीदी की रसोई' की सुविधा शुरू कर दी जाएगी, जिससे पुलिसकर्मियों को स्वच्छ भोजन मिल सके। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड को भी सामान्य पुलिसकर्मियों की तरह बीमा योजना का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है।

भालुओं के इंसानों पर हमले की घटनाओं से उत्तराखंड सरकार चिंतित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ऋषिकेश/भाषा। आधे से अधिक दिसंबर बीत जाने के बावजूद उत्तराखंड में अब तक भालुओं के शीतनिद्रा में नहीं जाने और आक्रामक होकर इंसानों पर हमला करने की कई घटनाओं के सामने आने से वन्यजीव विशेषज्ञ और राज्य सरकार चिंतित है।

वन्यजीव विशेषज्ञों ने बताया कि भालू और सर्प प्रजातियां सर्दियों में शीतनिद्रा काल में चली जाती हैं और यह इनकी सहज प्रवृत्ति है। उन्होंने बताया कि शीतनिद्रा काल में जाने से पहले इन प्रजातियों के जीवों द्वारा शरीर में चर्बी इकट्ठा करने के लिए प्रायः इनके व्यवहार में आक्रामकता देखी जाती रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि, ठंड के दौरान भालुओं के शीतनिद्रा में नहीं जाने तथा भ्रमणशील बने रहने जैसा असामान्य व्यवहार एक पहेली बन गया है। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत व्यापक कारण है जो अप्रत्याशित रूप से अपना असर छोड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भालुओं के इंसानों पर हमले की घटनाओं को चिंताजनक बताते हुए कहा कि जंगली भालुओं का यह समय गहन शीतनिद्रा काल में रहने का है लेकिन कुछ जगह वे खेत खलियानों में घूम रहे हैं। उनियाल ने कहा कि इसके कारणों की वजह जानने के लिए उत्तराखंड सरकार वन्यजीवों से जुड़े शोध संस्थानों से विस्तृत अध्ययन करवाएगी ताकि यह पता चल सके कि भालू अपने प्राकृतवासों में शीतनिद्रा काल में क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि अध्ययन रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर प्रदेश में इस जनसमस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। उनियाल ने वन विभाग को राज्य के जंगलों से सटे आबादी क्षेत्रों में सघन गश्त करने के भी निर्देश दिए हैं तथा जनता से भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है। प्रदेश के वन विभाग के प्रमुख (हॉफ) रंजन कुमार मिश्रा ने कहा कि भालुओं द्वारा हमले की अधिकांश घटनाएं संरक्षित वन क्षेत्रों से बाहर हुई हैं और इसकी समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जंगली भालुओं द्वारा वन क्षेत्र में स्थित अपने प्राकृतवासों को उपयोग में नहीं लाने के कारणों की जानकारी अध्ययन से ही पता चल पाएगी जिसके बाद उसके अनुसार कार्य योजना तैयार करके काम किया जाएगा।

बिहार में मजबूत और टिकाऊ सड़कें सरकार की प्राथमिकता: पथ निर्माण मंत्री

पटना/भाषा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ऐसी सड़कों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो लंबे समय तक टिकाऊ रहें और मौसम या भारी यातायात के बावजूद सुरक्षित बनी रहें।

जायसवाल यहां विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक कर प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति का गहन आकलन कर रहे थे जिसमें परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, समय-सीमा, निर्माण मानकों और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा, ''सरकार का संकल्प है कि आधुनिक और मजबूत अधोसंरचना के माध्यम से विकास की गति को और तेज किया जाए, ताकि जनता को सुरक्षित, सुगम और बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके।''

जायसवाल ने कहा कि राज्य में सड़क ढांचे को नई मजबूती देने की दिशा में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और सभी कार्य समय पर पूरे कराए जाएंगे। पथ निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क निर्माण में हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए, ताकि जनता का भरोसा और अधिक मजबूत हो सके। उन्होंने कहा, ''बिहार की सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं हैं, बल्कि राज्य के विकास की रीढ़ हैं। बेहतर सड़क नेटवर्क से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का संपर्क सुधरेगी तथा व्यापार, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और अधिक सुगम होगी।'' उन्होंने यह भी कहा, ''विभाग का ध्यान ऐसी सड़कों के निर्माण पर है, जो लंबे समय तक टिकाऊ रहें और मौसम या भारी यातायात के बावजूद सुरक्षित बनी रहें।''

जीतन राम मांझी के वीडियो से बिहार में फिर भड़का 'वोट चोरी' विवाद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार में उस वीडियो को लेकर एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कथित तौर पर विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से पीछे चल रहे एक उम्मीदवार की मदद करने की बात कहते नजर आ रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि वीडियो मांझी के लोकसभा क्षेत्र गया में बनाया गया है। यह वीडियो हाल में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार झेल चुके विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद)-कांग्रेस गठबंधन ने साझा किया है और इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) द्वारा वोट चोरी का सबूत बताया है।

हालांकि, मांझी ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है।

वीडियो में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री

एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) प्रमुख मांझी को टिकारी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी एक घटना का जिक्र करते हुए सुना जा सकता है। टिकारी सीट पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन पिछले महीने हुए चुनाव में वह राजद से हार गए। वीडियो में मांझी मगही बोली में यह कहते सुने जा सकते हैं, वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार 2,700 वोट से पीछे था। उसने मुझे फोन किया, मैंने संबंधित अधिकारी को फोन किया। आखिरकार उसे विजेता घोषित किया गया। 'पीटीआई-भाषा' इस वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका।

वीडियो में मांझी कहते सुने गए, इस बार उम्मीदवार 1,600 वोट से हार गया। लेकिन उसने मुझसे संपर्क करने के बजाय हार स्वीकार कर ली। गया के तत्कालीन जिलाधिकारी, जो अब त्रिपुरा में पदस्थापित हैं, ने मुझसे फोन पर पूछा कि इस बार क्या गड़बड़ी हुई। जब उम्मीदवार मुझसे संपर्क किए बिना घर लौट गया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने टिकारी सीट तो हासिल कर ली, लेकिन पांच साल पहले की 75 सीट की तुलना में इस बार महज 25 सीट पर सिमट गई। उसने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर यह वीडियो साझा करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता का सच करार दिया। विपक्षी दल राजद ने आरोप लगाया कि मोदी ने निर्वाचन आयोग की मदद से हालिया चुनाव में हमारे युवा और क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव की राजनीतिक हत्या का असफल प्रयास किया।

ओडिशा: संबलपुर में किसानों के बंद से जनजीवन प्रभावित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

संबलपुर/भाषा। ओडिशा के संबलपुर जिले में धान की शीघ्र खरीद की मांग को लेकर किसानों द्वारा आहूत बंद के कारण शुक्रवार को जनजीवन प्रभावित रहा। पुलिस ने बताया कि जिले में किसानों के प्रमुख संगठन 'संबलपुर जिला कृषक सुरक्षा संगठन' द्वारा आहूत यह बंद शांतिपूर्ण रहा और इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।

किसानों के समूह हाथ जोड़कर विभिन्न सरकारी कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से समर्थन मांगा। आंदोलन में शामिल एक किसान प्रफुल्ला स्वैन ने दावा किया, आम जनता और विशेष रूप से अधिकारी हमारे उद्देश्य के प्रति बहुत सहयोगी व सहायक रहे हैं। बंद के कारण सरकारी व निजी कार्यालय, बैंक व वित्तीय संस्थान, दुकानें, बाजार, मॉल और शोरूम बंद रहे।

शहर भर में कई स्थानों पर किसान शांतिपूर्ण धरना देते नजर आए। हालांकि, वाहनों की आवाजाही और आपातकालीन सेवाओं को बंद से छूट दी गई थी। बंद का असर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा गया। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया था तथा कोई नाकाबंदी नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों ने धान खरीद से संबंधित मुद्दों के स्थायी समाधान की मांग की।

संसद की प्रासंगिकता कम हो रही है, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक : सिब्बल

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को दावा किया कि संसद की प्रासंगिकता ''धीरे-धीरे कम हो रही है'' क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को इसकी ज्यादा परवाह नहीं है और वे सिर्फ उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो मौजूदा समय के लिए अप्रासंगिक हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए ''बेहद खतरनाक'' है क्योंकि संसद में वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती है।

निर्दलीय सांसद ने संवाददाताओं से कहा, ''मुझे लगता है कि हमारी संसद की प्रासंगिकता धीरे-धीरे कम हो रही है। अब कम बैठकें होती हैं और लोग सोचते हैं कि वहां कुछ नहीं होता है। यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती है। इसके बजाय, ऐसे विषय उठाए जाते हैं जो आज के समय के लिए अप्रासंगिक हैं।

बांग्लादेश में हालात के पीछे कट्टरपंथियों का हाथ : सिमक भट्टाचार्य

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सिमक भट्टाचार्य ने शुक्रवार को बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पड़ोसी देश में 'घटनाक्रम के पीछे कट्टरपंथियों का हाथ है'। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति पर उनका नियंत्रण है।

भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय स्थिति से उचित ढंग से निपट रहे हैं तथा वे उसी अनुरूप जवाब देंगे।

राज्यसभा सदस्य ने संवाददाता सम्मेलन में बांग्लादेश की स्थिति से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, बांग्लादेश में कट्टरपंथ और चरमपंथ कैंसर की तरह फैल रहा है। सभी सही सोच वाले लोगों को इस खतरे से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा,1980 के दशक से ही बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें अपनी जड़ें फैला रही हैं। यह हदें पार कर चुकी हैं। जैसा कि कल रात देखा गया, स्वतंत्र विचारक और उदारवादी व्यक्ति भी हमलों का शिकार हो रहे हैं। पूरी दुनिया कट्टरपंथ का खामियाजा भुगत रही है। एक राष्ट्रवादी सरकार और पार्टी ही इन चुनौतियों का सामना कर सकती है।

जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के बाद शुक्रवार को बांग्लादेश में तनाव फैल गया, जिस वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन, हिंसा और तोड़फोड़ हुई।

हालांकि, सुबह हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई लेकिन प्रदर्शनकारियों को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास, 32 धानमंडी की पहले से ही ध्वस्त इमारत में तोड़फोड़ करते देखा गया।

मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस द्वारा राष्ट्र को संबोधित एक टेलीविजन भाषण में इंकलाब मंच के नेता हादी की मौत की पुष्टि किए जाने के बाद बृहस्पतिवार रात को चटगांव स्थित भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पथराव सहित देश के विभिन्न हिस्से हमलों और तोड़फोड़ की घटनाओं से दहल गए।

जी राम जी विधेयक के बारे में गलत जानकारी फैला रहे राहुल गांधी : भाजपा

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद द्वारा पारित 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक' के बारे में 'गलत सूचनाएं' प्रसारित करने के बजाय खुद की जानकारी बढ़ानी चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को एक ही दिन में खत्म कर दिया और नया रोजगार गारंटी विधेयक ले आई। प्रतिक्रिया में भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक सामाजिक सुरक्षा नेट को हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें आधुनिक बनाने के बारे में है। मालवीय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''रोजगार, कौशल, बुनियादी ढांचे और जवाबदेही को मिलाकर, यह मनरेगा से आगे एक दूरदर्शी विकास का प्रतिनिधित्व करता है।''

ओडिशा में संपत्ति विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने दादी को वाहन से कुचला

जाजपुर (ओडिशा)/भाषा। ओडिशा के जाजपुर जिले में संपत्ति विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर वाहन से कुचलकर अपनी 70 वर्षीय दादी की हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना बृहस्पतिवार को पानीकोइली थाना क्षेत्र के अंतर्गत खंडारापुर-सिंगाडा गांव में हुई जब 23 वर्षीय आरोपी युवक ने अपनी दादी कुली साहू को वाहन से कुचल दिया। ग्रामीणों के अनुसार, महिला का बेटा उसकी देखभाल नहीं कर रहा था इस वजह से वह अपनी विवाहित बेटी के घर रहने पर मजबूर थी। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग महिला अपने बेटे द्वारा किए जा रहे शारीरिक और मानसिक शोषण से काफी परेशान थी।

अधिकारी ने कहा कि इस उत्पीड़न से तंग आकर महिला न केवल स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई बल्कि अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेटी के नाम कर दिया था, जिसके बाद संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। अधिकारी ने बताया कि घटना उस समय हुई जब महिला बेटी के साथ अपने पैतृक गांव लौट रही थी। उन्होंने कहा, पोते द्वारा वाहन से कुचले जाने से बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसकी बेटी बच गई। अधिकारी ने बताया कि आरोपी घटना के बाद वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मृतक की बेटी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

यह 'प्रदूषणकालीन सत्र' था, टैगोर के अपमान से शुरू और बापू के अपमान से खत्म हुआ : कांग्रेस

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने संसद का शीतकालीन सत्र संपन्न होने के बाद शुक्रवार को आरोप लगाया कि इस सत्र की शुरुआत सरकार द्वारा गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के अपमान से हुई और समापन ''महात्मा गांधी के अपमान'' से हुआ। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया यह शीतकालीन सत्र नहीं ''प्रदूषणकालीन सत्र'' था और वह सरकार वायु प्रदूषण पर चर्चा से भाग गई, जो यह मानती है कि वायु प्रदूषण का फेफड़े पर कोई असर नहीं होता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद रमेश ने संवाददाताओं से कहा, हमसे सर्वदलीय बैठक में कहा गया कि 14 विधेयक पेश होंगे, जिनमें दो विधेयक औपचारिकता निभाने वाले थे। यानी कुल 12 विधेयक की जानकारी दी गई थी। लेकिन इनमें से पांच विधेयक नहीं लाए गए। उन्होंने कहा कि 'वीबी जी राम जी विधेयक'' आखिरी दो दिनों में पेश किया गया। जी राम जी विधेयक पर लोकसभा में बुधवार देर रात तक चर्चा हुई, इसे बृहस्पतिवार को पारित किया गया, जबकि राज्यसभा में इस पर बृहस्पतिवार को करीब छह घंटे से अधिक की चर्चा के बाद 18 दिसंबर को देर रात पारित किया गया। रमेश ने दावा किया, इस सत्र की शुरुआत गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के अपमान से हुई... वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।

अब संयमित, आध्यात्मिक और परिपक्व क्रिकेटर इशान किशन की निगाहें भविष्य पर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। इशान किशन के हाव भाव में परिपक्वता साफ झलकती है क्योंकि झारखंड को पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दिलाने की खुशी और भारत की टी20 विश्व कप टीम चयन से एक दिन पहले उनके भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता दोनों पर उनकी प्रतिक्रिया एक समान ही है।

उनके पिता प्रणव पांडेय ने पीटीआई को बताया कि अब उनकी भावनाएं भगवद गीता के श्लोकों के अनुरूप हो गई हैं। किशन अब वर्तमान में जीते हैं और उनके लिए इस समय सबसे अहम है झारखंड की

मुश्ताक ट्रॉफी में जीत। किशन ने शुक्रवार को रांची हवाईअड्डे पर जोरदार स्वागत के बाद कहा, ''बहुत अच्छा खेले, बहुत मजा आया। आगे भी बात होगी और ऐसे ही जीतते रहेंगे। '' किशन की कप्तानी में झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में हरियाणा को 69 रन से हराया। बाएं हाथ के बल्लेबाज किशन टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, उन्होंने 10 पारियों में 57.44 के औसत और 197 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाए। फाइनल में किशन ने 49 गेंद में 101 रन की विस्फोटक पारी खेली और यह टूर्नामेंट में उनका पांचवां शतक था। इसके साथ ही उन्होंने भारत के टी20 सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की। वह अब बहुत शांत दिखते हैं और उनकी प्रतिक्रिया में दिखावा नहीं बल्कि सादगी थी। उन्होंने कहा, ''जीत अच्छी थी, बहुत खुशी हुई और जब टूर्नामेंट शुरू होंगे तो उसमें भी जीतकर आएंगे। '' इशान और झारखंड टीम का घर पर उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया।

नई श्रम संहिताएं रोजगार की प्रकृति, आर्थिक वृद्धि के लिए उपयुक्त : श्रम सचिव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय श्रम सचिव वंदना गुरनानी ने शुक्रवार को कहा कि हाल ही में लागू की गई चार श्रम संहिताएं रोजगार की मौजूदा प्रकृति और देश में हो रही आर्थिक वृद्धि के उपयुक्त हैं। गुरनानी ने यहां उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि नई श्रम संहिताएं एक गतिशील अर्थव्यवस्था के लिए रुख बदल देने वाले साबित होंगी। उन्होंने कहा कि पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर संबंधित नियमों को इन चार श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। इन कानूनों को 2019-20 में बनाया गया था और इन्हें 21 नवंबर, 2025 से लागू किया गया है।

गुरनानी ने कहा, ये कानून मौजूदा रोजगार की प्रकृति और भारत में देखी जा रही तेज आर्थिक वृद्धि के लिहाज से पूरी तरह उपयुक्त हैं। उन्होंने अनुपालन नियमों में ढील का उल्लेख करते हुए कहा कि पंजीकरण की संख्या आठ से घटाकर एक कर दी गई है, रिटर्न 31 से घटाकर एक और रजिस्टर 87 से घटाकर आठ कर दिए गए हैं। सचिव ने कहा कि नए श्रम कानून न्यूनतम वेतन, अनिवार्य नियुक्ति पत्र और श्रमिकों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। साथ ही निरीक्षक-आधारित मार्गदर्शन और आपराधिक दंड में कमी जैसे व्यापार-अनुकूल बदलाव भी किए गए हैं।

सुविचार

अभिमान नहीं होना चाहिए की मुझे किसी की जरुरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए की सब को मेरी जरुरत पड़ेगी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

पाकिस्तान के झूठ पर भरोसा क्यों?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में जो बयान दिया है, वह हकीकत से कोसों दूर है। वरिष्ठ नेताओं को बहुत सोच-समझकर बयान देना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अनर्गल बयान देकर पृथ्वीराज चव्हाण पाकिस्तान के मीडिया में छा गए हैं। वहां उनके शब्दों को सोशल मीडिया पर पेश कर पाकिस्तानी फौज के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। इसका फायदा भारत के दुश्मनों को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हो या दुनिया का कोई भी सैन्य अभियान, उसमें बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा ही रहती है। यह वीडियो गेम नहीं है, जिसे देखकर कोई कह दे, 'आनंद नहीं आया।' ऑपरेशन सिंदूर कितना असरदार था, यह जानना हो तो पाकिस्तान और पीओके के उन इलाकों के लोगों से पूछें, जहां भारतीय मिसाइलें गिरी थीं। अब तो ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। जब मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचीं तो आतंकवादियों और उनके कुनबों को संभलने का मौका नहीं मिला था। उन मिसाइलों की उत्कृष्टता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ध्वस्त ठिकानों के आस-पास स्थित इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और जो आतंकवादी चपेट में आया, वह ज़िंदा नहीं बचा। पाकिस्तानी फौज, आईएसआई और उनकी सरकार में खलबली मच गई थी। उनके नेतृत्व के पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। पाकिस्तान की जनता उन पर दबाव डाल रही थी कि जवाबी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जनता को भ्रमित करने के लिए फर्जी खबरें खूब फैलाईं। इतनी फैलाईं कि भारत के कुछ 'बड़े' चैनलों ने भी उन पर विश्वास कर लिया था। बाद में खुलासा हुआ कि यह पाकिस्तान का दुष्प्रचार था।

ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वीराज चव्हाण ने उन फर्जी खबरों को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया और अब तक उन पर विश्वास कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, इसका सही-सही आंकड़ा कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन वहां जिस तरह एंबुलेंसों से शव उतारे जा रहे थे, अस्पतालों की ओर भागमभाग मची थी और स्थानीय लोग सोशल मीडिया पर बता रहे थे, उससे आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि मारे गए आतंकवादियों की संख्या बहुत ज्यादा रही होगी। पाकिस्तानी फौजी भी बहुत ढेर हुए थे। अगर पड़ोसी देश यह स्वीकार कर ले तो जनता के सामने उसकी भारी किरकिरी होगी। पाकिस्तानी फौज ने बड़ी चालाकी से खुद की एक नकली छवि बना रखी है। करोड़ों पाकिस्तानी इस भ्रम में जी रहे हैं कि उनकी फौज ने हर युद्ध जीता था और वह अजेय है। सोशल मीडिया आने के बाद कई लोगों को पता चला कि पाकिस्तानी फौज ने कोई युद्ध नहीं जीता, बल्कि साल 1971 में तो उसने घुटने टेके थे। पाकिस्तानी नागरिक यह जानकर हैरान होते हैं कि साल 1999 में जब उनकी फौज कारगिल युद्ध हार गई थी तो अपने सैनिकों के शव लेने से भी इन्कार कर दिया था। उन्हें यह पढ़ाया गया था कि पाकिस्तानी फौज हर मोर्चा फतह करती जा रही थी! वास्तव में, पाकिस्तान को झूठ फैलाने में महारत हासिल है। उसने आईएसपीआर नामक झूठ की फैक्ट्री खोल रखी है, जिसका काम है झूठ का प्रचार-प्रसार करना। उसने सोशल मीडिया पर हजारों अकाउंट बना रखे हैं, जिन्हें इतने शातिर ढंग से संचालित किया जाता है कि बड़े-बड़े विशेषज्ञ धोखा खा जाते हैं। अब एआई की मदद से आईएसपीआर अपने झूठ को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए सावधान रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रसारित हर बात सच नहीं होती। वरिष्ठ नेता जब कोई बयान दें तो विश्वसनीय तथ्यों का अध्ययन जरूर करें।

ट्वीटर टॉक

राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) के राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में शामिल हुआ एवं शिक्षकों के हित, सम्मान और समस्याओं पर संवाद किया। उनकी भावनाओं और सुझावों को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनकर हर संभव सहायता व मजबूती से साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया।

-गोविंदसिंह डोटासरा

धौलपुर जिले के पचगांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण किया। साथ ही लखपति दीदी को ऋण सहायता चैक तथा टैबलेट का वितरण किया।

-भजनलाल शर्मा

बजरी से भरे डंपर के पलटने से टोंक निवासी 4 लोगों की मृत्यु एवं एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की खबर अत्यंत दुःखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को यह आघात सहने का संबल प्रदान करें।

-अशोक गहलोत

प्रेरक प्रसंग

प्रतिबद्धता

एक बार पं. बनारसीदास चतुर्वेदी जी के पास एक राजसी संदेश आया कि फलां-फलां जगह जितनी प्याऊ लगाई गई हैं उस संबंध में विस्तृत विवरण मधुकर पत्रिका में प्रकाशित किया जाये। लेकिन बनारसीदास जी ने साफ मना कर दिया और ओरछा नरेश को वापसी संदेश भेजकर पत्रिका का संपादन कार्य भी त्याग दिया। सन 1930 में उन्होंने ओरछा नरेश वीरसिंह जू देव के प्रस्ताव पर टीकमगढ़ जाकर 'मधुकर' नाम के पत्र का संपादन आरंभ किया था। नरेश ने उन्हें उनके निर्विघ्न व निर्बाध संपादकीय अधिकारों के प्रति आश्वस्त कर रखा था लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि राजा साहब 'मधुकर' को राष्ट्रीय चेतना की जगह 'दरबारी' ही बने रहने देना चाहते हैं, तो वह हट गये। प्रसिद्ध हिन्दी लेखक, पत्रकार, राज्यसभा सांसद, 'विशाल भारत' नामक हिन्दी मासिक के संपादक एवं साक्षात्कार की विधा को पुष्पित एवं पल्लवित करने वाले पद्मभूषण पं. बनारसीदास चतुर्वेदी जी एक समर्पित साहित्य सेवी थे। वह प्रतिदिन दर्जनों पत्र लिखा करते थे। उनका पत्र व्यवहार तथा विविध विभूतियों को लिखे गए पत्र आज भी पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं।

सामयिक

ओमान की तरफ से हाथ बढ़ाए जाने के बाद भारत ने भी अच्छी खासी छूट दी है. भारत अपनी 77.79 प्रतिशत टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी कम कर रहा है। यह ओमान से आयात किए जाने वाले सामान की 94.81 फीसदी वैल्यू कवर करता है। लेकिन संवेदनशील प्रोडक्ट्स के लिए भारत ने टैरिफ-रेट कोटा (टीआरक्यू) का तरीका अपनाया है, यानी लिमिटेड क्वांटिटी में ही कम ड्यूटी. कुछ अहम सेक्टर को इससे बाहर रखा गया है।

ओमान के साथ व्यापार समझौता, कितना फायदेमंद?

अशोक भाटिया

मोबाइल : 9221232130

पिछले दिनों ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर साइन करने के बाद भारत ने अब ओमान के साथ ऐसी ही डील पर साइन किये हैं। अमेरिका की तरफ से भारतीय एक्सपोर्ट पर 50 प्रतशित टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत सरकार की तरफ से इस तरह के एग्रीमेंट करने में तेजी लाई गई है। भारत और ओमान के बीच यह ऐतिहासिक समझौता गुरुवार यानी 18 दिसंबर को हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए। भारत का पिछले छह महीने के दौरान यह दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) है।

भारत-ओमान के बीच जिन वस्तुओं का कारोबार होगा उनमे प्रमुख जो है उसके अनुसार ओमान ने अपनी कुल शुल्क दरों की 98.08 प्रतिशत श्रेणियों पर शून्य-शुल्क पहुंच की पेशकश की है। इसमें ओमान को होने वाले भारत के 99.38 प्रतिशत निर्यात को हिस्सा शामिल है। पहली बार भारत की पारंपरिक औषधियों को शामिल किया गया है। इससे खाड़ी देशों में आयुष उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ेगी। रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, चमड़ा, जूते, खेल सामग्री, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, औषधि, चिकित्सीय उपकरण और मोटर वाहन सहित सभी प्रमुख श्रम-प्रधान क्षेत्रों को पूर्ण शुल्क समाप्ति का लाभ मिलेगा.97.96 प्रतिशत शुल्क श्रेणियों पर तत्काल शुल्क समाप्ति की पेशकश की जा रही है.भारत अपनी कुल शुल्क श्रेणियों (12,556) में से 77.79 प्रतिशत पर शुल्क उदारीकरण की पेशकश कर रहा है, जिसमें मूल्य के आधार पर ओमान से होने वाले भारत के 94.81प्रतिशत आयात शामिल है।

ओमान के लिए जिन उत्पादों में निर्यात रुचि है और जो भारत के लिए संवेदनशील हैं, वहां अधिकांश मामलों में शुल्क-दर कोटा (टीआरक्यू) आधारित शुल्क उदारीकरण की पेशकश की गई है। संवेदनशील उत्पादों जैसे कृषि उत्पादों (दुग्ध, चाय, कॉफी, रबर एवं तंबाकू उत्पाद सहित), सोना व चांदी उत्पादों, आभूषण, जूते, खेल सामग्री तथा कई आधारभूत धातुओं के कबाड़ पर पर कोई शुल्क रियायत नहीं। यूएसएफडीए, ईएमए और यूकेएमएचआरए सहित अन्य द्वारा स्वीकृत औषधि उत्पादों के लिए विपणन अनुमतियों की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। ओमान का वैश्विक सेवा आयात 12.52 अरब अमेरिकी डॉलर है, जबकि भारत की हिस्सेदारी मात्र 5.31प्रतिशत है। आंकड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए अपार अप्रयुक्त क्षमता को दर्शाते हैं.ओमान ने कंप्यूटर संबंधी सेवाओं, व्यापार एवं पेशेवर सेवाओं, ऑडियो-विजुअल सेवाओं, अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं।

ओमान ने पहली बार कुशल पेशेवरों की आवाजाही (मोड-4) के तहत व्यापक प्रतिबद्धताएं पेश की हैं, जिनमें कंपनी के भीतर स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों की सीमा को 207 से बढ़ाकर 507 कर दिया है। संविदा आधार पर सेवा प्रदान करने वालों के लिए ठहरने की स्वीकृत अवधि में भी वृद्धि की गई है। इसे मौजूदा 90 दिन से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया गया है. इसे दो वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। लेखांकन, कराधान, वास्तुकला और चिकित्सा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों के लिए अधिक उदार प्रवेश और ठहरने की शर्तें। सीईपीए के तहत ओमान के प्रमुख सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों द्वारा 1007 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रावधान है। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि ओमान की अंशदायी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू होने के बाद सामाजिक सुरक्षा समन्वय पर भविष्य में चर्चा की जाएगी। यह 2006 में अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद ओमान द्वारा किसी अन्य देश के साथ हस्ताक्षरित पहला द्विपक्षीय समझौता है.द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। ओमान खाड़ी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और पश्चिम एशिया पूर्व तथा अफ्रीका के व्यापक क्षेत्रों में भारतीय वस्तुओं व सेवाओं के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। ओमान में करीब सात लाख भारतीय नागरिक निवास करते हैं, जिनमें ऐसे भारतीय व्यापारी परिवार भी शामिल हैं जो 200-300 वर्ष से वहां रह रहे हैं। ओमान में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 6,000 से अधिक भारतीय प्रतिष्ठान हैं। भारत को ओमान से प्रतिवर्ष लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त होती है। ओमान के लिए यह 2006 के बाद किसी देश के साथ पहला ऐसा करार है। इस डील के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड, इनवेस्टमेंट और सर्विसेज को लेकर आने वाले समय में नई संभावनाएं बनेंगी। इस डील के साथ ही भारत की खाड़ी देशों में पहुंच मजबूत होगी और लाखों नौकरियों के मौके बनने की उम्मीद है।

एग्रीमेंट की बड़ी खासियत यह है कि ओमान ने भारत के निर्यात पर बड़ी छूट दी है। ओमान अपनी 98.08 प्रतिशत टैरिफ लाइन्स पर जीरो ड्यूटी देगा, जो कि भारत के एक्सपोर्ट का 99.38 प्रतिशत वैल्यू कवर करता है। इसमें से 97.96 प्रतिशत पर तुरंत ड्यूटी खत्म हो जाएगी। आसान भाषा में समझें तो भारतीय सामान ओमान में पहले से काफी सस्ते हो जाएंगे। इससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इससे टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, दवाइयां, मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ा फायदा होने वाला है.

जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भारत और ओमान के बीच हुई डील से बड़ा फायदा होने वाला है। दरअसल, ये सभी लेबर-इंटेंसिव सेक्टर हैं... जहां लाखों कारीगर, महिलाएं और छोटी इंडस्ट्री (चड्ढएी) काम करती हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस डील के बाद इन सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी और रोजगार के मौकों में भी इजाफा होगा. अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए जाने के बाद यह भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ा मौका है।

ओमान की तरफ से हाथ बढ़ाए जाने के बाद भारत ने भी अच्छी खासी छूट दी है. भारत अपनी 77.79 प्रतिशत टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी कम कर रहा है। यह ओमान से आयात किए जाने वाले सामान की 94.81 फीसदी वैल्यू कवर करता है। लेकिन संवेदनशील प्रोडक्ट्स के लिए भारत ने टैरिफ-रेट कोटा (टीआरक्यू) का तरीका अपनाया है, यानी लिमिटेड क्वांटिटी में ही कम ड्यूटी. कुछ अहम सेक्टर को इससे बाहर रखा गया है। इसका मकसद भारतीय किसान और इंडस्ट्री को सुरक्षित रखना है। इनमें डेयरी प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफी, रबर, टोबैको, गोल्ड-सिल्वर बुलियन, ज्वेलरी, फुटवियर, स्पोर्ट्स गुड्स और कई मेटल्स का स्क्रैप शामिल हैं। इस करार के तहत सर्विसेज सबसे अहम हिस्सा है. ओमान की तरफ से हर साल करीब 12.52 बिलियन डॉलर की सर्विसेज का आयात किया जाता है, लेकिन भारत का हिस्सा इसमें 5 प्रतिशत के करीब है।

इस सेक्टर से भारत को काफी उम्मीद है। ओमान ने पहली बार 127 सब-सेक्टर्स जैसे कंप्यूटर सर्विसेज, बिजनेस और प्रोफेशनल सर्विसेज, ऑडियो-विजुअल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस भारत को दिया है. इससे भारतीय कंपनियों को मौका मिलेगा और स्किल्ड जॉब्स में भी इजाफा होगा. आईटी, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में भारतीय प्रोफेशनल्स को फायदा होगा। बताया जाता है कि अपने हितों की रक्षा के लिए, भारत ने बिना किसी छूट की पेशकश किए संवेदनशील उत्पादों को बहिष्करण या नकारात्मक श्रेणी में रखा है। इसमें 2,789 टैरिफ लाइनें शामिल हैं। इस लिस्ट में डेयरी, चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू उत्पादों जैसे कृषि उत्पाद भी शामिल हैं; सोने और चांदी के बिस्किट, गहने, चॉकलेट और अन्य श्रम-प्रधान उत्पाद जैसे जूते-चप्पल, खेल का सामान और कई बेस मेटल का स्क्रैप शामिल है।

नजरिया

भाजपा का राजनीतिक भविष्य युवाओं के भरोसे

अजय कुमार

मोबाइल : 9335566111

राहुल गांधी जब भी सार्वजनिक मंच से बोलते हैं, तो ऐसा आभास देते हैं मानो अगला प्रधानमंत्री बनना अब बस औपचारिकता भर रह गया हो। लेकिन सियासत भावनाओं से नहीं, आंकड़ों और नतीजों से चलती है। 2014, 2019 और 2024 तीन लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं और तीनों में जनता ने राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद वे उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते दिखते हैं। राजनीति में रिटायरमेंट की कोई तय उम्र नहीं होती, लेकिन लोकतंत्र में जनता बार-बार किसी नेता को नकार दे, तो वह खुद एक बड़ा संकेत होता है। राहुल गांधी आज 55 वर्ष के हैं। अगर वे किसी सरकारी या गैर-सरकारी संस्था में होते, तो अगले पाँच साल में रिटायरमेंट की तैयारी शुरू हो जाती। राजनीति में वे रिटायर नहीं होंगे, लेकिन उनके सामने जो खतरे खड़े हो रहे हैं, वे अब नजरअंदाज करने लायक नहीं रहे। राहुल गांधी के स्वभाव और राजनीतिक शैली पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। नकारात्मक राजनीति उनके भाषणों का स्थायी हिस्सा बन चुकी है। कभी चौकीदार चोर है, कभी वोट चोर, कभी गद्दी छोड़ो हर चुनाव के बाद नया नारा, लेकिन नतीजा वही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार उन्हें हर हाल में चोर ही नजर आती है। समस्या यह नहीं कि वे सवाल उठाते हैं, समस्या यह है कि जनता को उनके सवालों में समाधान नहीं दिखता। विपक्ष की भूमिका निभाने और वैकल्पिक नेतृत्व देने के बीच जो फर्क होता है, राहुल गांधी आज भी उसी रेखा को नहीं पकड़ पाए हैं।

बीते महीनों में कांग्रेस के भीतर से ही जो आवाजें उठी हैं, वे राहुल गांधी की राजनीति के लिए नए खतरे का संकेत देती हैं। ओडिशा के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम का पत्र कोई मामूली घटना नहीं थी। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस युवाओं से कटती जा रही है और नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है। इसी पत्र में उन्होंने राहुल गांधी पर भी इशारों-इशारों में कहा कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस ने आत्ममंथन करने के बजाय मोकीम को निष्कासित कर दिया। यह वही पुरानी कांग्रेस है, जो आईना दिखाने वालों को बाहर का रास्ता दिखा देती है। इंडिया गठबंधन के भीतर भी राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर असहजता अब खुलकर दिखने लगी है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वोट चोरी के आरोपों को सार्वजनिक तौर पर खारिज कर दिया। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के बाद ही नेतृत्व परिवर्तन की बात कह चुकी हैं। शरद पवार, अखिलेश यादव और लालू यादव जैसे नेता भी निजी बातचीत में यही संकेत देते रहे हैं कि कांग्रेस को अब आत्मकेंद्रित राजनीति छोड़नी होगी। सवाल साफ है अगर अपने ही सहयोगी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो देश कैसे करेगा? राहुल गांधी खुद को युवाओं का नेता बताने की कोशिश करते हैं। वे जेन-जी की बात करते हैं, आंदोलन की वकालत करते हैं, सोशल मीडिया पर युवाओं को संबोधित करते हैं। लेकिन 2029 में जब अगला लोकसभा चुनाव होगा, तब राहुल गांधी 59 वर्ष के होंगे। जेन-जी वह पीढ़ी है, जिसकी उम्र आज 13 से 28 वर्ष के बीच है। यह मान लेना कि 60 के करीब पहुंचा नेता किशोरों और युवाओं की मानसिकता का नेतृत्व करेगा, सियासत की हकीकत से आंख चुराने जैसा है। युवाओं को केवल भाषण नहीं चाहिए, उन्हें अवसर, नेतृत्व और भविष्य की स्पष्ट तस्वीर चाहिए जो कांग्रेस आज तक नहीं दे पाई। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर युवा नेतृत्व की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। दिसंबर 2025 में बिहार के मंत्री और पांच बार के विधायक नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, यह एक राजनीतिक संदेश है। भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य की राजनीति युवाओं के कंधों पर लड़ी जाएगी। संगठन से लेकर सरकार तक, 50 से 55 वर्ष की उम्र के नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव ये सभी चेहरे दिखाते हैं कि भाजपा लंबी राजनीतिक पारी की तैयारी कर रही है।

कांग्रेस की हालत इसके ठीक उलट है। सचिन पायलट जैसे नेता सालों से इंतजार में हैं। कर्नाटक में डीके शिवकुमार आज भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। शशि थरूर को लोकप्रियता के बावजूद किनारे रखा गया। कन्हैया कुमार जैसे नेता इस्तेमाल से ज्यादा उपेक्षा के शिकार हुए। नतीजा यह हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, जयवीर शेरगिल जैसे युवा चेहरे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। कांग्रेस आज भी वरिष्ठता और परिवारवाद की दीवार में उलझी हुई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को युवा चेहरा कहा जाता है, लेकिन पार्टी के भीतर अंतिम फैसले आज भी सोनिया गांधी के इर्द-गिर्द घूमते हैं। कर्नाटक संकट हो या संगठनात्मक फेरबदल, आखिरी नजर उन्हीं पर जाती है। यह स्थिति उस पार्टी की है, जो खुद को लोकतंत्र की संरक्षक बताती है।

कांग्रेस का अंदरूनी कलह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से टकराव, बिना सहयोगियों को भरोसे में लिए राष्ट्रीय रैलियां, गठबंधन धर्म की अनदेखी ये सब राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष को जोड़ने का दावा करने वाले नेता के कदम अगर खुद बिखराव पैदा करें, तो खतरा स्वाभाविक है। सबसे बड़ा खतरा उम्र नहीं, बल्कि समय से तालमेल न बैठा पाना है। भाजपा जहां युवाओं को आगे कर रही है, वहीं कांग्रेस बूढ़ों की फौज बनती जा रही है। राहुल गांधी चाहे जितना युवा दिखने की कोशिश करें, सच्चाई यही है कि पांच साल बाद वे भी उसी कतार में होंगे, जिसकी ओर मोकीम ने अपने पत्र में इशारा किया था। भारतीय राजनीति अब धैर्य नहीं, दिशा मांगती है। जनता को सपना नहीं, रोडमैप चाहिए। राहुल गांधी आज भी संघर्ष और शिकायत के बीच फंसे हुए हैं। अगर यही रफ्तार रही, तो आने वाले सालों में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा विरोधी नहीं, बल्कि समय साबित होगा।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

भारत ने दिखाया कि परंपरा और विज्ञान साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं: डब्ल्यूएचओ शिखर सम्मेलन में टेड्रोस

नई दिल्ली/भाषा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने शुक्रवार को कहा कि स्वास्थ्य सेवा एकीकृत और समावेशी होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान और परंपरा एक-दूसरे के पूरक हैं। वह पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर बोल रहे थे। भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से आयोजित यह शिखर सम्मेलन बुधवार को शुरू हुआ था और इसमें 100 से अधिक देशों के मंत्री, वैज्ञानिक, नेता तथा विशेषज्ञ शामिल हुए।

भारत की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने यह साबित कर दिया है कि परंपरा और नवाचार साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा, ''भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।''

शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने कहा, ''पारंपरिक चिकित्सा हमारे आधुनिक विश्व के स्वास्थ्य के लिए कई खतरों, आर्थिक क्षमताओं पर बढ़ते बोझ और स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच को दूर करने में मदद कर सकती है।''

ईडी ने सट्टेबाजी मामले में युवराज सिंह, सोनू सूद व अन्य की संपत्तियां कुर्क कीं

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा के साथ ही तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती और अभिनेता सोनू सूद की संपत्तियों को एक 'अवैध' सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धनशोधन मामले में कुर्क कर लिया है, जिनकी अनुमानित कीमत 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अंतरिम आदेश जारी करने के बाद अभिनेत्री नेहा शर्मा, मॉडल एवं अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की मां एवं बांग्ला अभिनेता अंकुश हाजरा की संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है। उन्होंने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में सूद की लगभग एक करोड़ रुपए की, चक्रवर्ती की 59 लाख रुपए की, युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपए की, शर्मा की 1.26 करोड़ रुपए की, उथप्पा की 8.26 लाख रुपए की, हाजरा की 47 लाख रुपए की और रौतेला की मां की 2.02 करोड़ रुपए की संपत्तियां शामिल हैं।

क्रिसमस

उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन नई दिल्ली में उनके द्वारा होस्ट किए गए क्रिसमस लंच के दौरान स्टूडेंट्स के साथ।

प्रधानमंत्री की आठ पोस्ट सबसे ज्यादा 'रि-पोस्ट'

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आठ पोस्ट या तस्वीरें पिछले 30 दिन में सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पोस्ट में शामिल हैं। इनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कार में सफर करने की उनकी तस्वीर भी शामिल है।

इन आठ पोस्ट को 'एक्स' पर कुल मिलाकर 1,60,700 बार 'रि-पोस्ट' किया गया और उन्हें 14.76 लाख 'लाइक' मिले। इस तरह वह सोशल मीडिया मंच पर सबसे ज्यादा 'लाइक' और 'रि-पोस्ट' किए गए शीर्ष 10 हैंडल में शामिल होने वाले एकमात्र राजनेता बन गए हैं। एक अधिकारी ने बताया, ''एक्स (पहले ट्विटर) में एक नया फीचर शुरू किया गया है। यह किसी एक देश में पिछले महीने सबसे ज्यादा लाइक किए गए पोस्ट को दिखाता है। भारत के लिए, पिछले 30 दिन में, सबसे ज्यादा लाइक किए गए 10 पोस्ट में से शीर्ष 8 पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी के हैं। पुतिन के यहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार में यात्रा करने की तस्वीर को 34,000 से अधिक बार 'रि-पोस्ट' किया गया और 2,14,000 'लाइक' मिले - जो प्रधानमंत्री के आठ पोस्टों में सबसे अधिक है।

राहुल गांधी की पूर्व जर्मन चांसलर से मुलाकात, भारत-जर्मनी संबंधों को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जर्मनी के पूर्व चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात कर भारत और जर्मनी के संबंधों को मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा की है। राहुल गांधी ने जर्मनी के पर्यावरण मंत्री कार्स्टन श्नाइडर तथा कुछ स्थानीय विचारक संस्थाओं (थिंक टैंक) के लोगों से भी मुलाकात की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष इन दिनों जर्मनी के दौरे पर हैं।

कांग्रेस ने उनकी मुलाकातों की तस्वीरें जारी की हैं। मुख्य विपक्षी दल ने जर्मनी के पूर्व चांसलर से राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''राहुल गांधी ने जर्मनी के पूर्व चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ दोपहर के भोजन पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने वैश्विक मामलों, व्यापार और बदलती दुनिया में भारत-जर्मनी संबंधों को मजबूत करने के बारे में विस्तार से बातचीत की।'' कांग्रेस ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की श्नाइडर के साथ मुलाकात में जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौती और भविष्य के लिए टिकाऊ, जन-केंद्रित समाधान पर चर्चा की गई।

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' का फाइनल ट्रेलर रिलीज

मुंबई/एजेन्सी

21 साल की उम्र में पाकिस्तानी सीमा में घुसकर दुश्मनों का सफाया करने वाले सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'इक्कीस' का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर इतना धमाकेदार है कि अभिषेक बच्चन और नव्या नवेली नंदा खुद को इसकी तारीफ करने से नहीं रोक पा रहे हैं। दोनों ने ही अगस्त्य नंदा की फिल्म की तारीफ कर अरुण खेत्रपाल के जज्बे को सलाम किया है। अभिषेक बच्चन ने अपने भांजे अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' का फाइनल ट्रेलर शेयर किया है और फिल्म को सच्ची और जज्बे से भरी कहानी बताया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, एक अनकही सच्ची कहानी जिसे देखा जाना चाहिए।फिल्म 1 जनवरी को रिलीज होगी। जबकि अगस्त्य नंदा की बहन नव्या नवेली नंदा ने लिखा, 'फाइनल ट्रेलर आ गया है। इस नए साल, खुद को हिम्मत का तोहफा दें। सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता की सच्ची कहानी देखें, एक हीरो जो सिर्फ़ 21 साल का था और अमर हो गया, वे थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।'बात अगर ट्रेलर की करें तो फिल्म में अगस्त्य नंदा सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का रोल प्ले कर रहे हैं, जिन्हें भारतीय टैंकों का महारथी कहा जाता था। उन्हें टैंक से बहुत प्यार था और यही वजह थी कि उन्होंने आर्मी का हिस्सा बनने का सोचा। ट्रेलर में अगस्त्य नंदा की एक्टिंग दमदार लग रही है, वे जोशीले अंदाज में हर सीन को जीवंत कर रहे हैं।

ट्रेलर में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अरुण खेत्रपाल के पिता की भूमिका निभाई है। ट्रेलर में भावुक होकर वे अपने बेटे के शहीद होने की कहानी बताते हैं और कहते हैं कि 'काश वो उस वक्त पीछे हट गया होता।' बता दें कि भारत-पाकिस्तान के युद्ध के समय सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अकेले ही पाकिस्तान के 10 टैंकों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन हमले की वजह से टैंक में आग लग गई और अरुण खेत्रपाल शहीद हो गए।

मरणोपरांत उन्हें अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पहले फिल्म 25 दिसंबर, यानी आज ही रिलीज होनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' के जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए फिल्म की रिलीज को स्थगित कर दिया गया। अब फिल्म 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'हैप्पी पटेल' का ट्रेलर रिलीज

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड में आमिर खान की फिल्मों का हमेशा से अलग ही क्रेज रहा है। उनके नए प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार करने वाले दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। आमिर खान इस बार अपनी फिल्म में हीरो की भूमिका में नहीं, बल्कि बतौर निर्माता अपने बैनर आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत नई जासूसी कॉमेडी फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' लेकर आए हैं। मेकर्स ने शुक्रवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। ट्रेलर की शुरुआत ही दर्शकों को हंसाने और चौंकाने वाले अंदाज में होती है। इसमें अभिनेता वीर दास बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। वे एक ऐसे दिलचस्प जासूस के रूप में सामने आते हैं, जो

मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन की परीक्षा में सात बार फेल हो चुके हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि अचानक उन्हें पता चलता है कि उन्हें गोवा में एक मिशन पर भेजा जाता है।

मिशन का मकसद केवल इतना है कि वह स्थानीय लोगों में घुल-मिल जाएं, लेकिन काम शुरू होते ही मजेदार परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। उनकी हर कोशिश हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती है। ट्रेलर में कॉमेडी और हंगामे की झलक है। ट्रेलर में मोना सिंह भी अपने किरदार खलनायिका 'मामा' की भूमिका में नजर आईं। उनका नया हेयरकट और अनोखा अंदाज फिल्म में हटकर पहचान दिलाता है। वहीं, मिथिला पालकर फिल्म में वीर दास की गर्लफ्रेंड के रोल में हैं, जिनकी मासूमियत कहानी में हल्का-फुल्का रोमांस और मनोरंजन जोड़ती है।ट्रेलर के आखिर में इमरान खान का लुक दर्शकों को हैरान करने वाला है, जो दस साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं।

उनके साथ आमिर खान का कैमियो भी ट्रेलर में देखने को मिला, जो दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। ट्रेलर में तीनों अभिनेताओं का लुक और अंदाज दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं।फिल्म में कॉमेडी, जासूसी, मनोरंजन, पागलपन और अप्रत्याशित घटनाओं का बेहतरीन मिश्रण है।फिल्म के निर्माण की बात करें तो इसे आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है, जबकि कहानी वीर दास ने अमोघ रणदिवे के साथ मिलकर तैयार की है।फिल्म 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

यादों में नलिनी : ब्यूटी में मधुबाला को पछाड़ा, तीन दिन बाद चला मौत का पता

मुंबई/एजेन्सी

हिंदी सिनेमा में कुछ नाम ऐसे हैं, जिनकी चमक समय के साथ फीकी नहीं पड़ती। 40 और 50 के दशक की जानी-मानी अभिनेत्री नलिनी जयवंत भी उन्हीं नामों में शामिल हैं। एक ऐसा दौर था जब उनकी मुस्कान, अदाएं और सादगी ने लाखों दिलों को अपना दीवाना बना लिया था। उस समय उनकी खूबसूरती की तुलना मधुबाला जैसी महान अभिनेत्री से की जाती थी। यही नहीं, साल 1952 में जब एक लोकप्रिय फिल्म मैगजीन ने ब्यूटी पोल कराया, तो नलिनी जयवंत ने मधुबाला को पीछे छोड़ दिया। उस दौर में यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं मानी गई थी। नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई में हुआ था, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था। वह एक मराठी परिवार से थीं। उनके पिता कस्टम ऑफिसर थे और फिल्मों से जुड़ी दुनिया को पसंद नहीं करते थे। इसके बावजूद, नलिनी का झुकाव बचपन से ही संगीत और नृत्य की ओर ज्यादा था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग भी ली। उनका रिश्ता फिल्मी दुनिया से पहले से जुड़ा हुआ था। वह मशहूर अभिनेत्री शोभना समर्थ की चचेरी बहन थीं, जो अभिनेत्री तनुजा की मां थीं। तनुजा काजोल की मां हैं। इस तरह वह काजोल के परिवार का हिस्सा भी थीं।

नलिनी ने बहुत कम उम्र में फिल्मों में कदम रखा। साल 1941 में महबूब खान की फिल्म 'बहन' से उन्होंने बतौर अभिनेत्री अपनी पहचान बनाई। उस समय वह उम्र में छोटी थीं, लेकिन कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। फिल्मों में उनका अभिनय देख दर्शकों ने मान लिया था कि नलिनी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि एक

बेहतरीन अदाकारा भी हैं। धीरे-धीरे उनका नाम इंडस्ट्री में फैलने लगा।

1950 का दशक नलिनी जयवंत के करियर का सबसे चमकदार दौर रहा। अशोक कुमार के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। 'समाधि' और 'संग्राम' जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। साल 1950 में निर्देशक ज्ञान मुखर्जी की फिल्म 'संग्राम' में उन्होंने अपनी बोल्ड इमेज से खूब सनसनी मचाई थी। उस दौर में उनकी खूबसूरती इतनी मशहूर हो गई कि फिल्मफेयर मैगजीन के ब्यूटी पोल में उन्हें देश की सबसे सुंदर अभिनेत्री चुना गया।पोल में मधुबाला जैसी बड़ी स्टार को पीछे छोड़ना इस बात का सबूत था कि नलिनी जयवंत उस समय दर्शकों के दिलों पर राज कर रही थीं।

इसके बाद नलिनी ने 'जलपरी', 'सलोनी', 'काफिला', 'नाज', 'लकीरें', 'नौ बहार', 'शेरू' और 'मिस्टर एक्स' जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। वह सिर्फ अभिनय ही नहीं करती थीं, बल्कि कई फिल्मों में उन्होंने गाने भी खुद गाए।हालांकि समय के साथ फिल्म इंडस्ट्री बदलने लगी और 60 के दशक के बाद नलिनी को पहले जैसे रोल मिलने बंद हो गए। साल 1965 में फिल्म 'बॉम्बे रेस कोर्स' के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। करीब 18 साल बाद वह फिल्म 'नास्तिक' में नजर आईं, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह अभिनय से संन्यास ले लिया।

नलिनी जयवंत की निजी जिंदगी भी आसान नहीं रही। उन्होंने दो शादियां कीं, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। पहली शादी साल 1945 में निर्देशक वीरेंद्र देसाई से हुई, जो कुछ साल बाद टूट गई। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी 1960 में अभिनेता प्रभु दयाल से की।दूसरे पति प्रभु दयाल के निधन के बाद वह पूरी तरह अकेली हो गईं। 22 दिसंबर 2010 को 84 साल की उम्र में नलिनी जयवंत का निधन हो गया। उनकी मौत का पता तीन दिन बाद चला।

विरोध

महात्मा गांधी की ड्रेस पहने एक आदमी और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस सेवादल के सदस्य कोलकाता में शुक्रवार को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की जगह लेने वाले विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल के विरोध करते हुए।

साान्या मल्होत्रा को 'मिसेज' के लिए मिला अवॉर्ड

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा के लिए दिसंबर का महीना लकी साबित हो रहा है। इस महीने उन्हें एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग अवॉर्ड से नवाजा गया है। अभिनेत्री को भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सान्या ने खुशी जाहिर करते हुए फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट की। सान्या मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार के साथ फोटो पोस्ट की। अभिनेत्री हाथ में आईटीए की ट्रॉफी और चेहरे पर स्माइल लिए दिख रही हैं। यह अवॉर्ड उन्हें ओटीटी फिल्म 'मिसेज' के लिए मिला। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''दिल कृतज्ञता से भरा है। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, 'मिसेज' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस।'' इस फिल्म में सान्या ने ऋचा नाम के गृहिणी का रोल प्ले किया है। उनके साथ निशांत दहिया और कंवलजीत सिंह भी नजर आए थे। फिल्म से हर महिला ने कनेक्ट किया है। फिल्म गृहिणी की रोजमर्रा के काम और परेशानियों को दिखाती है कि कैसे पढ़ी-लिखी होने और पूरी मेहनत के बाद भी वे ससुराल वालों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पातीं। फिल्म में बहुत छोटे-छोटे पहलुओं पर गौर किया गया है, जैसे सिलबट्टे की चटनी ज्यादा अच्छी होती है, आलू ज्यादा उबल गए हैं, या खाने में नमक कम है। इन चीजों से हर महिला को कभी न कभी दो-चार होना पड़ता है। फिल्म में परिवार, रिश्ते और परंपरा की दौड़ में महसूस होने वाली घुटन को अच्छे से पर्दे पर उतारा गया है। दो दिन पहले ही इसी फिल्म के लिए सान्या को फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड से नवाजा गया था। फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड में भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का ही अवॉर्ड मिला। उन्होंने खुशी जाहिर कर लिखा था, रिचू, तुम कितनी कमाल की लड़की हो, मेरी जिंदगी में आने और मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए थैंक यू। 'मिसेज' मेरे लिए बहुत खास है और यह अवॉर्ड मेरी टीम और मेरी शानदार कास्ट और क्रू के लिए है, जिन्होंने रिचा को जिंदा करने में मेरी मदद की। बता दें कि फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर रिलीज की गई थी और रेटिंग के मामले में दर्शकों ने ढेर सारा प्यार लुटाया था।

'होमबाउंड' के आस्कर नामांकन के लिए देश की दुआयें चाहते हैं :करण जौहर

मुंबई/भाषा। फिल्म निर्माता करण जौहर ने बृहस्पतिवार को कहा कि सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर श्रेणी में छांटी गई शीर्ष 15 फिल्मों में होमबाउंड को स्थान मिलना अपने आप में एक उपलब्धि है और अब टीम को उम्मीद है कि यह फिल्म ऑस्कर नामांकन हासिल करके भारत को गौरवान्वित करेगी।

इस फिल्म के निर्माता जौहर और अदार पूनावाला का 'धर्मा प्रोडक्शन्स' है जबकि इसका निर्देशन नीरज घेवान ने किया है।

जौहर ने कहा कि इस श्रेणी में शीर्ष 15 फिल्मों में पहुंचने पर उन्हें खुशी और घबराहट दोनों महसूस हो रही है। उन्होंने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा, यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है।

अभिनेत्री श्रीलीला ने एआई के दुरुपयोग पर जताई नाराजगी

मुंबई । सोशल मीडिया पर एआई का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ यह तकनीक जीवन को आसान बना रही है, तो दूसरी ओर इसके गलत इस्तेमाल से कई लोगों की छवि को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसकी चपेट में मनोरंजन जगत के सितारे भी पीछे नहीं हैं। डीप फेक कंटेंट से परेशान कई सेलेब्स ने इसको लेकर आवाजें भी उठाई हैं। इसी कड़ी में साउथ सिनेमा की अभिनेत्री श्रीलाला ने नाराजगी जताते हुए बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया। इसमें उन्होंने सभी से निवेदन किया कि बढ़ते एआई फेक वीडियो या किसी भी प्रकार के कंटेंट का समर्थन न करें। उन्होंने लिखा, मैं हाथ जोड़कर सभी से निवेदन करती हूं कि कृपया एआई द्वारा बनाई गई गलत और फेक चीजों का समर्थन न करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और उसका दुरुपयोग करने में जमीन-आसमान का फर्क है। मेरी नजर में टेक्नोलॉजी का उद्देश्य जिंदगी को आसान बनाना है, न कि उसे और भी ज्यादा मुश्किल करना।उन्होंने आगे लिखा कि दुनिया की हर लड़की किसी की बेटी, बहन, पोती या दोस्त होती है, भले ही वह फिल्म इंडस्ट्री में काम क्यों न कर रही हो। हम सब एक ऐसे माहौल में काम करना चाहते हैं, जहां पर खुशी फैले और हर कोई सुरक्षित महसूस करे।श्रीलीला ने खुलासा किया कि व्यस्त शेड्यूल की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर चल रही बातों की जानकारी देर से प्राप्त हुई। इसी के साथ अभिनेत्री ने अपने फैंस और शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें अलर्ट किया।

द्वारकादास गोवर्धनदास वैष्णव कॉलेज के एम बी ए विभाग द्वारा प्रथम जयगोपाल गाड़ोदिया एंडोमेंट व्याख्यान का आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां द्वारकादास गोवर्धनदास वैष्णव कॉलेज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने चेन्नई के जयगोपाल गाड़ोदिया फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए जयगोपाल गाड़ोदिया अक्षय निधि व्याख्यान के पहले संस्करण का आयोजन कॉलेज प्रेक्षागृह में 19 दिसम्बर को आयोजित किया। जयगोपाल गाड़ोदिया फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी सेवा संस्थान है जो मानवतावादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। प्रबंध न्यासी अशोक केड़िया, और जेजीजी फाउन्डेशन के ट्रस्टी एरा. मेयप्पन ने इस अक्षयनिधि को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने द्वारकादास गोवर्धनदास वैष्णव कॉलेज के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को उदारतापूर्वक योगदान दिया। इस एंडोमेंट व्याख्यान के पहले सत्र की अध्यक्षता सुनील गावंडे, डायरेक्टर और सीईओ और संजय कुंभार, डब्बावाला एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के प्रवक्ता न की। इस मौके पर कॉलेज के सचिव डॉ. अशोक कुमार मूँधड़ा सचिव, प्रबंध न्यासी जयगोपाल गाड़ोदिया फाउन्डेशन और कोषाध्यक्ष वैष्णव कॉलेज अशोक केडिया, जेजीजी फाउन्डेशन के ट्रस्टी एरा. मेयप्पन, कॉलेज के कैप्टन डॉ. एस संतोष बाबू और डॉ. यू अमलेश्वरी की गरिमामय उपस्थित रही।

कॉलेज परिसर में छात्रों को डब्बावाला सिस्टम के बारे में अत्यन्त गरिमामय जानकारीपूर्ण सत्र को आयोजित किया ताकि वे जानकारीपूर्ण दृष्टिकोण, परिवर्तनकारी अनुभव और प्रभावशाली प्रबंधन प्रथाओं को साझा कर सकें जो संगठनात्मक विकास और स्थिरता को आकार देते हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे डब्बावाला सिस्टम सिर्फ एक फूड डिलीवरी सेवा से कहीं ज़्यादा है और मानवीय जुड़ाव और सरलता की स्थायी शक्ति के माध्यम से मुंबई की सामुदायिक भावना और दक्षता का प्रतीक है।

सभी संतापों का नाश करती है श्रीमद्भागवत : प्रियशरण महाराज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। अन्ना नगर स्थित एसआरकेके अग्रवाल सभा भवन में चल रही कथा के दूसरे दिन कथा वाचक प्रियशरण जी महाराज ने शुकदेव जन्मोत्सव, परीक्षित जन्म की कथा को विस्तार से बताते हुए कहा कि श्रीमद्भागवत कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति के सभी संतापों का नाश हो जाता है। उन्होंने कहा कि जिस किसी पर ठाकुरजी कृपा होती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज हम सभी पर ठाकुरजी की असीम कृपा के कारण ही उनकी कथा का श्रवण कर पा रहे है क्योंकि जिन्हें ठाकुर जी जितना प्रदान करते है उसे उतना ही प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि अगर आप भागवत कथा सुनकर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ सीखना चाहते है तो कथा में प्यासे बन कर आए। कुछ सीखने के उद्देश्य से, कुछ पाने के उद्देश्य से आएं। यह कथा आपको बहुत कुछ देगी। उन्होंने कहा कि भागवत सब का सदैव कल्याण करती है। उन्होंने कहा कि बिना जाति और बिना मजहब देखे कथा श्रवण करने से मनवांछित फल मिल ही जाता है और अगर कोई कुछ न मांगे तो उसे मोक्ष पर्यंत तक की यात्रा कराती है। इस अवसर पर कथा आयोजक मोहन लाल सर्राफ, राजेंद्र गुप्ता, सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

एमजीएम हेल्थकेयर द्वारा जटिल हृदय विकार का सफलतापूर्वक इलाज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। एमजीएम हेल्थकेयर के डाक्टरों ने जटिल हृदय रोग से पीड़ित साठ वर्षीय मरीज का सफलतापूर्वक इलाज किया, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर (एवी) ब्लॉक के कारण खतरनाक रूप से कम हृदय गति (ब्रेडीकार्डिया) से पीड़ित थे। एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हृदय का एक दुर्लभ और उच्च जोखिम वाला विद्युत चालन विकार है। मरीज का आपातकालीन एवीआईआर डीआर प्रत्यारोपण किया गया, जो एक वास्तविक ड्यूल-चैंबर लीडलेस (वायरलेस) पेसमेकर है। यह अगली पीढ़ी की न्यूनतम इनवेसिव प्रक्रिया है जो वर्तमान में भारत में केवल कुछ ही केंद्रों पर उपलब्ध है।

यह प्रत्यारोपण एमजीएम हेल्थकेयर, चेन्नई के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, स्ट्रक्चरल और एंडोवास्कुलर इंटरवेंशन विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. बाबू एझुमलाई के नेतृत्व में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट की एक टीम द्वारा किया गया इस अवसर पर डॉ. बाबू एझुमलाई ने कहा कि पारंपरिक पेसमेकरों के विपरीत, जिनमें लीड और सर्जिकल पॉकेट की आवश्यकता होती है, एवीआईआर डीआर, एक सच्चा ड्यूल-चैंबर लीडलेस (वायरलेस) पेसमेकर है, जिसमें सर्जिकल चीरों की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे लीड और सर्जिकल पॉकेट से संबंधित जटिलताओं से बचा जा सकता है। यह प्राकृतिक एट्रियोवेंट्रिकुलर सिंक्रोनी को बनाए रखते हुए संक्रमण के जोखिम को कम करता है। सफल परिणाम जटिल हृदय लय विकारों के सुरक्षित और प्रभावी प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक ड्यूल-चैंबर लीडलेस पेसिंग तकनीक को अपनाने के महत्व को रेखांकित करते हैं। आज तक देश भर में इस तरह के केवल सीमित संख्या में प्रत्यारोपण किए गए हैं।

नेशनल हेराल्ड मामले में अगले सप्ताह दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश होंगे शिवकुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेलगावी। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि वह नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के तहत दिल्ली पुलिस को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए अगले सप्ताह उसके समक्ष पेश होंगे। दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के तहत वित्तीय और लेनदेन संबंधी विवरण के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार को नोटिस जारी किया था।

शिवकुमार ने एक सवाल पर पत्रकारों से कहा, मैंने उनसे कहा था कि मैं विधानसभा सत्र के बाद अगले सप्ताह आऊंगा। मैं जरूर जाऊंगा। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के नोटिस में कहा गया कि शिवकुमार के पास कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इस साल तीन अक्टूबर को दर्ज किए गए नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होने की संभावना है। ईओडब्ल्यू ने 29 नवंबर को जारी नोटिस में शिवकुमार को 19 दिसंबर तक उसके समक्ष पेश होने या मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा था। शिवकुमार ने कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस से प्राथमिकी की प्रति मांगी थी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र येडीयुरप्पा द्वारा उन्हें भ्रष्टाचार का पितामह कहे जाने के बारे में पूछे गए एक प्रश्न पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें समय पर जवाब दिया जाएगा। शिवकुमार ने कहा, विजयेंद्र को जवाब दूंगा...उन्होंने हमें (राज्य कांग्रेस सरकार को) कांग्रेस पार्टी का एटीएम कहा है। उन्हें इसे साबित करना होगा। इसलिए मुझे जो कहना था कह दिया है। वह कैसे कह सकते हैं कि यह एटीएम है और आरोप लगा सकते हैं कि खजाने खाली किए जा रहे हैं और पैसा (कांग्रेस आलाकमान को) भेजा जा रहा है? समय आने पर मैं उन्हें जवाब दूंगा।

विजयेंद्र ने उपमुख्यमंत्री द्वारा उन्हें वसूली का राजा कहे जाने पर पलटवार किया था, और कांग्रेस सरकार पर पार्टी आलाकमान को धन देने के लिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।

एसआरएमआईएसटी और अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेद ने हाथ मिलाए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कट्टंकुलाथुर। एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एसआरएमआईएसटी) के अनुसंधान निदेशालय के अंतर्गत अंतरविषयक भारतीय चिकित्सा प्रणाली संस्थान (आईआईएसएम) ने अमृता विश्व विद्यापीठम के अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेद के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है । इस समझौता ज्ञापन से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में अकादमिक सहयोग और अंतःविषयक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

इस सहयोग के अंतर्गत, दोनों संस्थान संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों, स्नातक और स्नातकोत्तर शोध परियोजनाओं, संकाय और शोधार्थियों के आदान-प्रदान, संयुक्त प्रकाशनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं और जनसंपर्क गतिविधियों पर मिलकर काम करेंगे। सहयोग के क्षेत्रों में आयुर्वेद, औषध विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, आणविक जीवविज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और भारतीय चिकित्सा प्रणालियों से संबंधित अन्य अंतःविषयक क्षेत्र शामिल हैं।

गुरु गणेश सेवा समिति का अमावस्या महाप्रसादी कार्यक्रम सम्पन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर की गुरु गणेश सेवा समिति कर्नाटक द्वारा शुक्रवार को स्व. रणजीतमल कांनूगा की स्मृति में समिति के मासिक सदस्यों की ओर से अमावस्या अन्नदान कार्यक्रम में मैसूर बैंक सर्कल के पास हनुमान मंदिर के सामने हजारों लोगों को भोजन करवाया गया । समिति के कार्याध्यक्ष आशीष बाफ़ना ने बताया कि इस सेवा कार्य में चेयरमैन गौतमचंद धारीवाल की उपस्थिति में कोषाध्यक्ष मनोहरलाल बाफना, महावीर धारीवाल, मनु बाफ़ना, विनोद चौरड़िया, प्रकाश बाफना, यशवंत सालेचा, राजू आंचलिया, अनिल पोकरणा आदि ने अपनी सेवाएं दी। समिति के कोषाध्यक्ष मनोहरलाल बाफना ने बताया कि इस कार्यक्रम में कार्याध्यक्ष आशीष बाफ़ना द्वारा समिति को एक वर्ष हेतु अन्नदान के लिए अर्थ सहयोग प्रदान करने के लिए उनका सम्मान किया गया।

कर्नाटक की जेलों में प्रतिबंधित वस्तुओं के खिलाफ तलाशी अभियान तेज किया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (कारागार) आलोक कुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की जेलों में प्रतिबंधित वस्तुओं के खिलाफ तलाश अभियान तेज कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कई चीजें जब्त की गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 36 घंटे में कलबुर्गी, मंगलुरु और शिवमोगा समेत विभिन्न जेलों के अंदर तलाश अभियान के बाद मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। डीजीपी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, राज्य में जेल परिसरों में प्रतिबंधित वस्तुओं के खिलाफ हमारा तलाश अभियान जारी है। पिछले 36 घंटे में कलबुर्गी में 10 मोबाइल फोन और चार सिम कार्ड, मंगलूरु में छह फोन, बेल्लारी में चार फोन और शिवमोगा जेलों में तीन फोन और चार सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। यह अभियान जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि बेंगलूरु की परप्पना अग्रहारा जेल के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी के तहत बृहस्पतिवार देर रात चलाए गए एक अभियान में 30 मोबाइल फोन जब्त किए गए। कुमार ने कहा, हम एसपी अंशु कुमार और जेलर शिवकुमार द्वारा किए गए अच्छे काम की सराहना करते हैं, जिन्होंने तलाश दल का नेतृत्व किया। तलाश दल के लिए 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

संत महापुरुषों के उपदेशों से ही जीवन का सही मार्गदर्शन संभव : साध्वी भव्यगुणाश्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के मागड़ी रोड स्थित गुरु ज्येष्ठ पुष्कर आराधना केंद्र में विराजित साध्वी भव्यगुणाश्रीजी ने कहा कि सत्संग हमेशा सकारात्मक ऊर्जा तो देता ही है, साथ ही हमारा यश भी बढ़ाता है। ऐसे में धार्मिक स्थलों और तीर्थों को ऊर्जा का केन्द्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो ऊर्जा इन जगहों पर रहती है, वह और कहीं नहीं पाई जाती, यही कारण है कि इन स्थानों पर जाकर मनुष्य का मन शांत और ऊर्जावान हो जाता है। इन स्थानों पर जाने वाला व्यक्ति हमेशा ऊर्जा और सकारात्मक सोच से भरा होता है, इसलिए हमें सत्संग की घड़ी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संत महापुरुषों की शिक्षाओं व उपदेशों से ही जीवन का सही मार्गदर्शन संभव है। बहुत से संत, महापुरुषों द्वारा दिए गए जीवन के विचारों के साथ मानवता के कल्याण का रास्ता मिलता है। ङ्कसाध्वी शीतलगुणाश्रीजी ने कहा कि हमारे जीवन में सत्संग का बहुत महत्व है। महापुरुषों द्वारा बताए गए मार्ग पर चल कर जो प्रेरणा मिलती है उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। लोगों को ऐसे धार्मिक समागमों में बढ़-चढ़ कर शामिल होने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि महापुरुषों के प्रवचन हमारे जीवन को सही दिशा देने में बहुत सहायक हो रहे हैं।

महापुरुषों का चिंतन सांसारिक लोगों से भिन्न होता है, क्योंकि वह जब भी सोचते है तो शुभ ही सोचते हैं, इंसानियत के भले के लिए ही सोचते है। जहां इंसान चिंता को चिंतन समझने की भूल कर बैठता है, वहीं महापुरुषों के चिंतन में चिंता का हरण करने वाले प्रभु ही होते है। सांसारिक चिंतन को हम चिंतन की परिभाषा दे सकते हैं। आज हम संसार की ओर नजर दौड़ाकर देखें तो आज प्रत्येक मानव बुरे चिंतन की आग में झुलस रहा है। आज प्रत्येक इंसान दूसरे इंसान को पछाड़ कर आगे निकलना चाहता है, चाहे इसके लिए किसी भी सीमा को क्यों न पार करना पड़े। हमारे महापुरुष जिस शुभ चिंतन की बात करते हैं उसे जानकर हमें महान व्यक्तित्व के दर्शन हो जाते हैं।

शुभ चिंतन का अर्थ जो प्रभु के साथ मिलने के पश्चात सोचा जाए। फिर ऐसे चिंतन में से स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ की महक आती है। फिर दूसरों का भला करने से भी सुकून की प्राप्ति होती है। हमेशा परोपकार के कार्य करें तो भगवान की कृपा हासिल होती है और इंसान प्रभु परमात्मा से जुड़ता है। उसकी जिंदगी से मुश्किलों और कठिनाइयों का अंत होता है और वह भवसागर से पार हो जाता है।

'ओगार्ड वारियर्स टीम' ने जीती डीडीएच बॉक्स क्रिकेट लीग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हुब्बल्ली। शहर के स्पोर्ट्स पार्क में बुधवार को डीडीएच क्रिकेट कमेटी द्वारा आयोजित डीडीएच बॉक्स क्रिकेट लीग 3 में 'ओगार्ड वारियर्स टीम' विजेता बनी। इस बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट में बारह टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला ओगार्ड वारियर्स एवं टर्फ टाइटन टीम के बीच हुआ जिसमें ओगार्ड वारियर्स टीम ने खिताब अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में 173 रन बनाकर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब नरेश वेदमुथा को मिला एवं 6 विकेट लेकर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की ट्रॉफी धनराज सेठ को मिली। मुख्य प्रायोजक शांतिदेवी सुमेरमल ओबानी परिवार ने विजेता टीम को ट्रॉफी भेंट की। इस अवसर सभी लाभार्थियों एवं टीम मालिकों का कमेटी द्वारा सम्मान किया गया। मैच में कमेंट्री संजय सेठ एवं विक्रम मांडोत ने की। सचिन संघवी ने सबको धन्यवाद दिया।

ईडी ने पूर्व मंत्री नागेंद्र की आठ करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने कथित वाल्मीकि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी. नागेंद्र की लगभग आठ करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। कुर्क की गई संपत्तियों में चार आवासीय व व्यावसायिक भूखंड और एक इमारत शामिल हैं।

ईडी ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई है। संघीय जांच एजेंसी ने इन संपत्तियों को अपराध से अर्जित आय बताया। ईडी के बयान में कहा गया है कि अपराध से अर्जित शेष धनराशि का पता नहीं लगाया जा सका है और ऐसा प्रतीत होता है कि बी. नागेंद्र ने या तो इसे खर्च कर दिया है या छिपा दिया है। ईडी के अनुसार, अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 8.07 करोड़ रुपये है। धन शोधन का यह मामला कर्नाटक पुलिस और सीबीआई की एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खातों से करोड़ों रुपये की धनराशि को फर्जी खातों में अंतरित किया गया और बाद में फर्जी संस्थाओं के माध्यम से धन शोधन किया गया।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Aditya at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.